लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 46—सोमवार, 25 अप्रैल, 1966/5 वैशाख, 1888 (शक)

No. 46—Monday April 25, 1966/Vaisakha 5, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बधी उल्लेख	Obituary Reference	7237–38

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.			
1307	फाजिल्का क्षेत्र से लापता हुए व्यक्तियों की वापसी	Recovery of Missing Persons from Fazilka Sector . . .	7238–40
1308	आकाशवाणी के महानिदेशक	Director General of A.I.R.	7240–43
1309	विद्रोही नागा	Naga Hostiles . . .	7243–46
1310	जवानों के बच्चों के लिए सुविधाएं	Facilities to Children of Soldiers	7246–48
1311	राष्ट्रमण्डल	Commonwealth . . .	7248–50

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1312	सैनिक कर्मचारियों के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Army Personnel	7250
1313	ब्रिटेन की राजनीति में जातिवाद की समस्या	Racial Problem in British Politics	7250
1314	उपग्रहों के माध्यम से टेलिविजन व्यवस्था	Television, through Satellites	7251
1315	रंगून में नेताजी का मकान	Netaji's House in Rangoon .	7251
1316	सांस्कृतिक भाषा के रूप में अंग्रेजी	English as a Cultural Language	7251
1317	पत्रिकाओं का प्रकाशन	Publication of Journals . .	7252
1318	सिक्किम में कागज की लुगदी की परियोजना	Paper Pulp Project in Sikkim .	7252
1319	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीयों की मृत्यु	Death of Indian Internees in Pakistan	7252–53
1320	मिजो पहाड़ियों में अशान्ति के कारण शरणार्थियों का पूर्वी पाकिस्तान में जाना	Movement of Refugees into East Pakistan on account of Unrest in Mizo Hills	7253

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1321	चीन द्वारा पाकिस्तान को 10 करोड़ डालर की सहायता	Chinese 100 Million Dollars aid to Pakistan . . .	7253
1322	वियतनाम	Vietnam	7254
1323	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electronics Ltd., Bangalore	7254–55
1324	प्रादेशिक सेना के कर्मचारी	Territorial Army Personnel .	7255
1325	पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित भौगोलिक प्रकाशन	Geographical Publications Published by East German authorities	7255–56
1326	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की कार्य-प्रणाली	Working of Indian Missions Abroad	7256
1327	आत्म निर्णय का सिद्धान्त	Principle of Self-Determination .	7256–57
1328	टेलीविजन सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Report on Television . . .	7257
1329	विदेशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Pakistan's Anti-Indian Propaganda Abroad . . .	7257
1330	दिल्ली छावनी क्षेत्र	Delhi Cantonment Areas . .	7257–58
1331	भारतीय समाचारपत्रों के बारें में पाकिस्तान का आरोप	Pak Allegation about Press in India	7258
1332	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धनसंग्रह	National Defence Fund Collections in U.P. . . .	7259
1333	सशस्त्र सेनाओं में कनिष्ठ कर्मचारी	Junior Employees in Armed Forces	7259

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4299	'इण्डियन रेयर अर्थज लिमिटेड'	Indian Rare Earths Ltd . .	7259–60
4300	भारतीय प्रेस परिषद्	Press Coucilof India . . .	7260
4301	आकाशवाणी, जयपुर के कलाकारों को वेतन	Salary to A.I.R. Artistes, Jaipur	7260
4302	आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र के आर्टिस्ट	A. I. R. Artistes of Jaipur Station	7261
4303	हैदराबाद तथा विजयवाड़ा आकाशवाणी केन्द्रों के आर्टिस्ट	A. I. R. Artistes of Hyderabad and Vijayawada Stations .	7261–62
4304	आकाशवाणी के आर्टिस्ट, आन्ध्र प्रदेश	A. I. R. Artistes, Andhra Pradesh	7262
4305	राजस्थान में सामुदायिक रेडियो सेट्स	Community Radio Sets in Rajasthan	7263
4306	श्रीलंका में राष्ट्रकताहीन भारतीय लोगों के बच्चे	Children of Stateless Indians in Ceylon	7263

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4307	भागलपुर में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Bhagalpur	7263
4308	भारत-पाकिस्तान संघर्ष सम्बन्धी रूपक (फीचर)	Features on Indo-Pakistan Hostilities	7264
4309	गाजियाबाद के निकट सड़क निर्माण	Construction of Road Near Ghaziabad	7264
4310	ब्रिटेन, अमरीका और रूस के लिये पारपत्र	Passports for U. K., U.S.A. and U.S.S.R.	7264
4311	गणतन्त्र दिवस, 1966	Republic Day, 1966	7265
4312	सामुदायिक रेडियो सेट	Community Radio Sets	7265
4313	उत्तर प्रदेश में आयुध कारखाना	Ordnance Factory in U.P.	7265
4314	जाली पासपोर्ट पर गुरदासपुर के श्री देवेन्द्र कुमार की ब्रिटेन की यात्रा	Travel of Shri Davendra Kumar of Gurdaspur to U. K. on Forged Passport	7265–66
4315	ऐसी समितियां तथा संविहित निकाय जिनमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीश कार्य करते हैं	Committees and Statutory Bodies in which Chief Justice and Judges of Supreme Court serve	7266
4316	उड़ीसा के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश	Newsprint Quota for Orissa	7266
4317	विदेशों में भारतीय भाषायें बोलने वाले लोग	Persons in Foreign Countries speaking Indian Languages	7267
4318	नेपाल को सहायता	Assistance to Nepal	7267
4319	दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना	Air Accident near Delhi	2768
4320	जाली पासपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति की गिरफतारी	Arrest of Passport Forger	2768
4321	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये मलयालम फिल्म	Malayalam Film for International Film Festival	7268–69
4322	पठानकोट-कांगड़ा सड़क पर सैनिक ट्रक की दुर्घटना	Military Truck Accident on Pathankot-Kangra Road	7269
4323	राष्ट्रीय रक्षा (नेशनल डिफेंस) कालेज, कनाडा	National Defence College, Canada	7269
4324	आइजल में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Aijal	7269–70
4325	दारेस्सलाम में भारतीय उच्चायुक्त का निवास स्थान	Residence of Indian High Commissioner in Dar-Es-Salaam	7270
4326	विदेशों में भारतीय मिशनों की देख-रेख	Maintenance of Indian Missions Abroad	7270–71
4327	गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में मिलिटरी स्कूल	Military School at Ghazipur (U.P.)	7271

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4328	छावनी बोर्ड	Cantonment Boards . . .	7271–72
4329	दिल्ली छावनी में भमिगत नाली व्यवस्था	Underground Drainage in Delhi Cantonment . . .	7272
4331	उड़ीसा में आकाशवाणी के द्वारा आदिमंजातीय लोकगीतों का प्रसारण	Broadcast of Tribal Folk Songs by the A.I.R. in Orissa .	7272–73
4332	रेडियो स्टेशन, जयपुर (उड़ीसा)	Radio Station, Jeypore (Orissa) .	7273
4333	जयपुर (उड़ीसा) आकाशवाणी केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट	A.I.R. Staff Artistes of Jeypore Section	7273
4334	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाएं	National Defence Academy Examinations	7274
4335	रेडियो सेटों की मांग	Demand for Radio Sets . .	7274
4336	प्रादेशिक सेना के कर्मचारी (पेंशन सम्बन्धी लाभ)	Territorial Army Personnel (Pensionary Benefits) . . .	7275
4337	प्रादेशिक सेना के अधिकारी	Territorial Army Officers . .	7275
4338	इजराइल के राष्ट्रपति के साथ कथित अशिष्टता	Reported Discourtesy to President of Israel . . .	7275–76

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में—

Re. Motion for Adjournment and Calling Attention Notices—

23 अप्रैल, 1966 को तिनसुकिया-न्युजलपाईगुड़ी सवारी गाड़ी में विस्फोट

Explosion in Tinsukia—New Jalpaiguri Passenger Train on 23-4-66: . . . 7276–77

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table . 7277

प्राक्कलन समिति—

Estimates Committee—

एकसौएकवां प्रतिवेदन

Hundred and First Report . 7277

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इकतीसवां प्रतिवेदन

Committee on Public Undertakings—

Thirty-first Report . . 7278

पंजाब सीमा आयोग तथा भारत रक्षा नियमों सम्बन्धी संकल्प के बारे में

Re : Resolution on Punjab Boundary Commission and Defence of India Rules . . . 7277

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—

Re : Calling Attention Notices—

आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नज़रबन्दों को रिहा किया जाना

Lifting of Emergency and Release of D.I.R. Detenus . 7278–80

अनुदानों की मांगें—

Demands for Grants—

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय—

Ministry of External Affairs—

श्री अन्सार हरवानी

Shri Ansar Harvani . . 7280

श्री फ्रैंक एंन्थनी

Shri Frank Anthony . . . 7280–81

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	7281–83
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	7283–84
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	7284–85
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	7285–86
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	7287
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	7288
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	7289–90
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	7290
श्री हेडा	Shri Heda	7290–91
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	7291–92
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	Shri Brajeshwar Prasad	7292–93
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	7393
लुमडिंग तथा डीफ रेलवे स्टेशनों पर हाल के विस्फोटों से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motion re. Situation arising out of recent Explosions at Lumding and Diphu Railway Stations—	
श्री स० का० पाटिल	ShriS.K. Patil	7293–95
श्री रंगा	Shri Ranga	7295–96
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	7296–97
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	7297
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	7297–98
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	7298–99
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	7299
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav	7299–7300
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	7300
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	7301
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah	7301–02
श्री स्वैल	Shri Swell	7302
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	7303
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	7303
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	7303–04
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	7304

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 25 अप्रेल, 1966/5 वैशाख, 1888 (शक)
Monday, April 25, 1966/Vaisakha 5, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि 22 अप्रैल, 1966 को नई दिल्ली में श्री राजेन्द्र सिंह का निधन हो गया है ।

श्री राजेंद्र सिंह 1957 से 62 तक की अवधि में दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : श्री राजेन्द्र सिंह के निधन के समाचार से सबको धक्का पहुंचा है। हमें उनकी मृत्यु पर आश्चर्य होता है क्योंकि वह जवानी में ही चल बसे हैं। वह एक नौजवान और हंसमुख व्यक्ति थे ।

मुझे आशा है कि हमारे जवान मित्र के निधन पर आप इस सभा के सभी दलों की ओर से उनके परिवार के प्रति सहानुभूति और संवेदना का संदेश पहुंचा देंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अपने अच्छे साथी के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार एक बात की जांच करे। जिस रोग से वह पीढ़ित थ, अस्पताल में ठीक समय पर दाखिल किये जाने के बावजूद उसका उचित निदान नहीं किया गया और इसी कारण उनका देहान्त हो गया। वह एपेन्डीसाइटिस रोग से पीड़ित थे, जो फट गया था और मृत्यु का कारण बना। हम विशेष रूप से चाहते हैं कि सरकार इस मामले की जांच करे ।

Shri Bagri (Hissar) : On behalf of my party and myself I express our condolences and deep sympathies at the passing away of Shri Rajendra Singh. Deaths, which take place due to the negligence of doctors leave disgust among the people. An enquiry should be made into this matter.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : एक अत्यन्त प्रिय सहयोगी के आकस्मिक निधन पर हम गहरा शोक और दुःख व्यक्त करते हैं । वह प्रगतिशील विचार वाले गतिशील व्यक्ति थे और संसद् सदस्य के रूप में वह सदा ही सक्रिय कार्य करते रहे। हमें जो प्रारंम्भिक जानकारी मिली है उससे

यह संकेत मिलता है कि डाक्टरों ने उनके लिये यथासंभव सब कुछ करने का प्रयत्न किया। डाक्टरों की लापरवाही के बारे में जो विशेष रूप से कहा गया या है उसके बारे में हम जांच करेंगे ।

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

The memebers then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फाजिल्का क्षेत्र से लापता हुए व्यक्तियों की वापसी

+

*1307. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सु० ला० वर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाजिल्का क्षेत्र से लापता हुए 6 दर्जन व्यक्ति पाकिस्तान से वापिस ले लिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं तो, उन व्यक्तियों को पाकिस्तान से वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सितंबर में भारत–पाकिस्तान की लड़ाई के बाद फाजिल्का क्षेत्र से 117 भारतीय राष्ट्रिक लापता बताये गये थे । उनमें से 116 व्यक्ति 23 दिसंबर, 1965 को भारत वापस आ गये थे। बाकी एक व्यक्ति का सवाल पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the steps being taken by the Government for his repatriation? What is coming in the way of his repatriation and whether he is not in Pakistan or that Govt. refuse to repatriate him?

Mr. Speaker : He has told that out of 117 missing persons, 116 have come.

श्री स्वर्ण सिंह : 7 अप्रैल, 1966 को पंजाब सरकार ने हमें यह सूचित किया कि फाजिल्का क्षेत्र से एक व्यक्ति अब भी लापता है। उस व्यक्ति का नाम गुरुदित्त सिंह है। हमने पाकिस्तान सरकार को कहा है कि वह इस व्यक्ति को वापस लौटा दे किन्तु पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

Shri Bagri : May I know the basis of this figure and whether it includes those persons also who were killed during, the Indo-Pakistan hostilities and whose dead bodies were not found and who were reported missing?

Shri Swaran Singh : The total number of persons, missing was 117 and out of them, one person has not returned. Those who were killed and whose dead bodies were not found are not included in it.

Shri Bagri : During the Indo-Pakistan conflict, when attack was launched in that Sector, a large number of persons including men, women and children were killed and their dead bodies were taken away by Pakistanis and all of them were reported missing. In this context, may I know the basis on which this figure has been calculated?

श्री स्वर्ण सिंह : इन व्यक्तियों में से 53 आदमी, 28 औरतें और 35 बच्चे ऐसे थे जिन्हें सितम्बर में हुए हिन्दुस्तान-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पंजाब की सीमा पर फाजिल्का क्षेत्र से पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया था और नजरबन्द रखा गया था। इन व्यक्तियों को 23 दिसम्बर, 1965 को भारत वापस लौटा दिया गया। यह सूचना विभिन्न रूप से उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था नजरबन्द रखा गया था और बाद में वापस लौटा दिया गया था।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has stated that the name of the missing person is Gurdit Singh. May I know whether Government were unaware of the fact that one person was still to be repatriated at the time when exchange of prisoners took place between India and Pakistan; if not, what action has been taken for his repatriation?

Shri Swaran Singh : Government were aware of this fact, and however 116 of them were repatriated; and it is hoped that these remaining persons would also be repatriated.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether Government have any information regarding the nature of treatment meted out to these 116 persons and also the nature of inquiries that were made from these persons?

Shri Swaran Singh : I have no information about these things at present if Pakistan had done such things.

श्री हेम बरुआ : भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इन 117 व्यक्तियों में से कितनी औरतें थीं जिन्हें पाकिस्तानी अपहरण कर के ले गये थे और क्या वापस की गई इन औरतों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उन्हें दी गयी यातना के बारे में सरकार को कोई कहानी सुनाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि मुझे इन बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन व्यक्तियों से किस प्रकार के सवाल पूछे गये अथवा ऐसी पूछताछ के दौरान इन व्यक्तियों ने क्या क्या बयान दिये ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government have tried to ascertain the reasons for his detention by Pakistan; if so, what reply has been given by Pakistan; and whether he is an officer or a big man?

Shri Swaran Singh : He is not a Government employee. But every Indian national, whosoever he may be, is a big man, whether he is an officer or not. However it has no concern with the matter. So far as reply from Pakistan about this man is concerned, they have not given any information so far.

श्री प्र० चं० बरुआ : असैनिकों विशेषत: औरतों का अपहरण करने का उद्देश्य स्पष्टत: अनतिक उद्देश्य था जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा हेग कन्वेन्शन के विरुद्ध है। क्या इन बातों को उठाया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसके कानूनी पहलू पर मैं कोई राय व्यक्त नहीं करूंगा किन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे उस विशिष्ट कानूनी पहलू के बारे में जानकारी दें, जिसका उल्लेख किया गया है, तो मैं इस पर आगे विचार करूंगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि पंजाब सरकार तथा सेना के अधिकारी इन साक्षियों पर निरंतर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वे इन दो अभिकरणों द्वारा स्थापित जांच निकाय को कोई ऐसी बात न बतायें, जिससे कि कठिनाई पैदा हो जाये; यदि हां, तो क्या इस शरारत को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात का पक्का विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है (अन्तर्बाधायें) मुझ एसे किसी दबाव के बारे म कुछ भी पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य ने मुझ यह बात पहले बताई होती, तो मने यह सुनिश्चित कर दिया होता कि वास्तविक तथ्यों को दबवाने के लिये किसी पर कोई दबाव न डाला जाये ।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री जी को पता है कि जिम्मेदार व्यक्तियों ने इस बात की शिकायत पहले ही कर दी है कि ऐसा किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को पता नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य के पास इस बारें में कोई सूचना हो तो कृपया वह मेरे पास भिजवा दें ।

श्री दाजी : हमारी धारणा यह है कि भारत सरकार पाकिस्तान से वापस आने वाले कैदियों से उन हालातों तथा व्यवहार के बारे में कोई पूछताछ नहीं करती, जिनमें उन्हें रखा गया था और जो उनके साथ किया गया था । क्या पूछताछ करने का मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है अथवा केवल इसी मामले में भारत सरकार उदासीन रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : आमतौर पर कायदा यह है कि सुरक्षा दल तथा पुलिस के वापस लौटाये गये । इन कैदियों से नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आम नागरिकों के बारे में भी सामान्य पूछताछ की जाती है । किन्तु इस विशेष मामले में क्या क्या पूछताछ की गई है, इस बारे में जब तक मैं खुद ही संतुष्ट न हो जाऊं, मैं अनुमान लगाना नहीं चाहता ।

Director-General of A. I. R.

+

***1308. Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the reasons why the Director-General, All India Radio is continuing in his post despite the contrary advice given by the U. P. S. C.; and

(b) the reasons for the delay in appointing a suitable person to this post and when this appointment is likely to be made?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Smt. Nandini Satpathy) : (a) The present Director-General is being continued with the concurrence of the U. P. S. C. until a regular selection is made by the Commission.

(b) The post has already been advertised by the U. P. S. C. and regular appointment will be made as soon as the selection has been completed.

Shri Bhagwat Jha Azad : Despite the contrary advice given by the U.P.S.C., why the present Director-General is allowed to continue ? I want clarification on this point.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : So at as our knowledge goes, it is no doubt a fact that he has not been selected not on the ground that he is not competent and fit for the post but because of the fact that certain adverse entries were there in his record and the Promotion committee of the U. P. S. C. had observed that although he is adept in his subject, he could not be selected on the basis of these adverse remarks. **(Interruptions).** I am giving full information, when it was imperative to fill up this post and hence advice of the U.P. S. C. was sought as to whether he could be allowed to continue till a final selection was made. The Commission gave their approval.

श्री शिंकरे : इस मामले पर सरकार को संघ लोक सेवा आयोग की राय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

Shri Raj Bahadur : He has been appointed in the officiating capacity for the period till a final selection is made.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether after his rejection by the U. P. S. C., more than once, the Govt. was unable to find even one suitable person in all its departments for this particular post; and had it become necessary for the Government to make a reference to the U.P. S. C. again for his appointment; and if so, whether it is not a fact that political intrigues are on the increase in A.I.R. after this Director-General has taken over this assignment?

Shri Raj Bahadur : The impression of the hon. Member, that this officer had been rejected twice is not correct**(Interruptions)**. The names of three persons were referred to, when this post fell vacant after Shri Bhatt's appointment somewhere else. None of them was found fully competent for the post.

So far as the second part of his question relating to suitability or this post is concerned, selection for filling up the post is done by three methods, namely, by promotion, by selection from amongst Class I Senior I.A.S. or I.C.S. officers and third one is by way of direct recruitment. Now selection is being made on the basis of direct recruitment.

About politics, which he has mentioned, I deny that charge.

श्री स० चं० सामन्त : उन्हें इस पद पर रखे रहने के बजाये इस विभाग में पद के लिहाज से जो व्यक्ति उनके बाद आता है, उसे अस्थायी तौर पर संभालने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राज बहादुर : इस पद के लिये कुछ विशेष अर्हताओं की आवश्यकता होती है **(अन्तर्बाधाएं)** हमें संघ लोक सेवा आयोग की राय के आधार पर चलना होता है **(अन्तर्बाधाएं)** । उक्त आयोग ने अपनी राय व्यक्त कर दी है--**(अन्तर्बाधाएं)** । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि कम से कम में सं० लो० से० आयोग मैं फैसला करने वाला नहीं हूं--इस पद के लिये जिन आदमियों के नामों पर विचार किया गया था। उनमें एक डा० मेनन हैं, दूसरे श्री मलिक जिनके बारे में यह समझा गया कि वह पद के लिये उपयुक्त नहीं है और तीसरा व्यक्ति परिवीक्षा (प्रोबेशन पर थे। इसलिये श्री सामन्त द्वारा पूछे गये अगले व्यक्ति के बारे में विचार नहीं किया जा सका ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether it is a fact that an able man like Shri Bhatt was transferred from this department only with a view to appointing this man as Director-General ?

Shri Raj Bahadur : Somehow or other, it is simply their opinion and it is not correct. Shri Bhatt was transferred as Chairman of the Central Board of Film Censors.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस मामले से संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त, क्या सरकार आकाशवाणी के महानिदेशक के पद के दर्जे को ऊंचा करने तथा आकाशवाणी के समूचे संगठन को सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से उच्चतम पद-स्थिति के व्यक्ति की सेवायें प्राप्त करने के संबंध में निश्चय कर सकी है ? क्या सरकार इस दृष्टि से इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है अथवा केवल इस अथवा उस व्यक्ति की नियुक्ति के ही बारे में विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : कार्यवाही के लिये यह एक सुझाव है जिस पर उस समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जायेगा जिसके माननीय सदस्य स्वयं एक सदस्य थे। वर्तमान स्थिति यह है कि इस पद के लिये आवेदन पत्र भेजने वाले लोगों में से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती की जायेगी ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न मामला है। उस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं बहुत दुःख के साथ यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्योंकि यह भावना केवल आकाशवाणी के क्षेत्रों में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी दिन-प्रतिदिन बल मिलता जा रहा है कि यह नियुक्ति सरासर भाई-भतीजा बाद के आधार पर की गई है।

इस धारणा को यथाशीघ्र दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : तथ्य ये हैं। स्थान रिक्त हो गया है। भर्ती का एक तरीका अर्थात् लोक संघ सेवा आयोग की समिति द्वारा अगले कनिष्ठ अधिकारी का पदोन्नत किया जाना, अपनाया गया। अतः भाई-भतीजावाद का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक किसी धारणा को दूर करने का संबंध है, वह एक व्यक्तिनिष्ठ मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल संघ लोक सेवा आयोग पर ही निर्भर करेंगे। हम इसका अपमान नहीं करेंगे और संघ लोक सेवा आयोग जिस की व्यक्ति को चुनेगा हम उसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra: Just now the Hon. Minister has replied that the U.P.S.C. found two or three shortcomings in that person. In view of this, will he be able to discharge his duties properly and if not, why did the Government not immediately appoint such a person who did not suffer from any short comings for that post?

Shri Raj Bahadur : I have not said of shortcomings. I said that there was some objectionable entry in his record and therefore he was not taken. Despite that entry, tne U. P. S. C. sanctioned his appointment tentatively after that he successfully went through the ordeal of Indo-Pakistani Conflict **(Interruptions.)** Now it is a matter of opinion as to in what esteem he is held by different persons.

Shri Buta Singh : While replying the hon. Minister has said that below the name of Shri Bhatt there were the names of three other officers which were not sent to the U. P. S. C. May I know whether these remarks of the Minister will bias the judgement of the U. P. S. C., when this case is again referred to U.P.S.C.?

Shri Raj Bahadur : That cannot happen, because U. P. S. C. is an independent body.

विद्रोही नागा

+

***1309. श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 को ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन समाचारों की पुष्टि अथवा खण्डन कर सकती है कि विद्रोही नागाओं ने राकेट चलाये थे; और

(ख) यदि उन्होंने राकेट चलाये थे, तो उन्हें ये राकेट तथा उन्हें चलाने वाले हथियार कहां से प्राप्त हुए थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नागा विद्रोहियों ने 29 नवम्बर को धनसिरी रेलवे स्टेशन के निकट मुसाफर गाड़ी पर 73 एम० एम० राकेट से 27 गोलियां चलाई।

(ख) अभी तक उस संसाधन का पता नहीं लग पाया जिस द्वारा विद्रोही नागाओं ने वह हथियार प्राप्त किया जो फ्रांसीसी निर्माण का एक स्ट्रिम प्रकार का राकेट है।

Shri Madhu Limaye : It is repeatedly appearing in the press that Naga and Mizo hostiles are receiving training and weapons from Pakistan. Will Government lay a white paper in this regard?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह एक ऐसा मामला है जिस पर बड़ीगम्भीरता से विचार किया जायेगा और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम समूचे मामले की जांच करेंगे।

Shri Madhu Limaye : When our relations with Pakistan get strained, only then we are reminded of the independence of Pakhtoonistan and East Bengal. The policy of Pakistan towards our country is to destroy our sovereignty and they are trying for that and assisting rebellious tendencies in this country. In view of this, may I know whether our Government will make it firm policy to assist the democratic forces in Pakistan?

श्री अ० म० थामस : नागा विद्रोहियों के दलों के द्वारा हमारे क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में जाना तथा वहां से हथियार और गोलाबारुद ले कर वापस लौटने के संबंध में हमने पाकिस्तान सरकार को दो विरोधपत्र लिखे हैं। दोनों अवसरों पर पाकिस्तान सरकार ने तथ्यों को मानने से इन्कार किया है और उनको निराधार बताया है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, अर्थात् पखतूनिस्तान आन्दोलन को सहायता देने का, हम नहीं समझते कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है।

Shri Madhu Limaye : What is this reply?

Mr. Speaker: He says that the question of giving assistance to the movement of Pakhtoonistan is a matter of broad policy and that this does not arise out of this question. A separate notice may be given for this.

Shri Madhu Limaye : This matter was first raised in a Calling Attention Notice. At that time the hon. Defence Minister had said that there was such apprehension and that full information will be collected. Now it can be inferred that they are being given assistance. So, have we any policy to deal with such situations ?

Mr. Speaker : Policy can not be discussed through a supplementary question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Just now the hon. Minister stated that the rockets were not supplied to Nagas by Pakistan Government.....

श्री अ० म० थामस : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : He has said that.

Mr. Speaker : Protest has been made in regard to the Nagas who had gone to Pakistan and came back bringing arms with them. But, Pakistan Government has denied that and described them as baseless allegations.

Dr. Ram Manohar Lohia : Pakistan Government had denied other facts but not regarding rockets. These rockets were supplied to Nagas either by Pakistan Government or by Burma Government or Indian Government or these were dropped for Nagas by some foreign Power. The hon. Minister must reply to any of the possibilities.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बात यह है कि यद्यपि हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि ये राकेट कहां से आये। फिर भी हम स्थिति को देखते हुए निश्चय ही अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान से आये हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागा विद्रोही पाकिस्तान गये वहां पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और पाकिस्तानी हथियार लेकर वापस लौटे। सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि आप जानते हैं नागाओं के पाकिस्तान जाने, वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और हथियार लेकर लौटने के संबंध में हमने समय समय पर जानकारी दी है। हम इसको बन्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी हमें आंशिक रूप से सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती।

Shri Rameshwaranand : The reply of Pakistan to our protests that they never supplied arms to Nagas and that these were baseless allegations. Will the Government of India be ever able to make arrangements to unveil the truth?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बात यह है कि जब भी हम सरकारी अथवा राजनयिक स्तर पर इस प्रश्न को उठाते हैं तो हमें हमेशा नकारात्मक उत्तर मिलता है। इन हथियारों को देने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार नहीं की है। स्वभावत:, एक सरकार के रुप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। लोगों को बाहर जाने से रोकें या जब लोग जाकर वापस आये तो उनको आने से रोकें या उनको पकड़ें और उनको दण्ड दें। इस मामले में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री रा० बरुआ : विद्रोही नागाओं के एक वर्ग ने अब एक नई चाल अपनाई है और यह है मैदानी क्षेत्रों में संचार साधनों तथा पूर्वी प्रदेश के राजनीतिक जीवन को भंग करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को यह पता है कि समूचे मामले में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है और यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नागाओं का यह प्रश्न, विशेष रूप से ये कार्यवाहियां जो उनके द्वारा की गई थीं अथवा की जा रही हैं निरन्तर सरकार के विचाराधीन हैं। इन मामलों की जांच अभी की जा रही है। परन्तु उनकी चाल निश्चय ही आन्तरिक संचार साधनों तथा आन्तरिक जीवन को भंग करने की है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार जानती है कि चीनी नेताओं के हाल के पूर्वी पाकिस्तान के दौरे के दौरान नागा विद्रोहियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमण्डल मार्शल चेन यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो से ढाका में मिला था, यदि हां, तो क्या सरकार ने पता लगाया है कि जिन विषयों पर वहां चर्चा की गई और क्या यह चर्चा नागा विद्रोहियों को अधिक हथियार देने के संबंध में थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे मंत्रालय में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से मैं इस ब्यौरे को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री हेम बरुआ : मैं ने यह जानकारी दी है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान में स्थित हमारे राजनयिक सूत्रों से इन तथ्यों की पुष्टि की है। अब वह कहते हैं कि वह नहीं जानते। फिर वह क्या जानते हैं ? वे कुछ जानने का प्रयत्न नहीं करते। वे देश का सत्यानाश होने दे रहे हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उन्होंने कुछ तथ्यों को प्रकट किया है और वह चाहते हैं कि मैं उनकी पड़ताल करूं। मैं निश्चय ही इनकी पड़ताल करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत यह है कि यह जानकारी कुछ समय पूर्व प्राप्त हुई थी और सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या सरकार ने राजनयिक सूत्रों से इसकी पुष्टि की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे याद नहीं कि माननीय सदस्य ने एक बार भी मुझ से या और किसी से इसका उल्लेख किया है। नागा विद्रोहियों और मार्शल चेन यी के बीच भेंट की बात मैं पहली बार सुन रहा हूं। यह सच है कि नागा समय समय पर हमारे देश से पाकिस्तान जाते रहे हैं। जो भी जानकारी उपलब्ध होती थी उसे हमने हमेशा देने का प्रयत्न किया है। अतः यह आशा नहीं की जा सकती कि मुझे सारी बातों का ज्ञान हो। उन्होंने यह जानकारी अब दी है। वह बाहर भी मुझे इसके बारे में बता सकते थे और मैं उसका सत्यापन कर सकता था।

श्री हेम बरुआ : तो क्या मैं यह समझूं कि जो चीज समाचारपत्रों में नहीं आती सरकार को उसका पता नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका सत्यापन करेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को यह पता लगा है कि ये हथियार और राकेट नागाओं को कौन देश दे रहे हैं; अथवा उन हथियारों की प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों के बाद भी सरकार यह पता नहीं लगा पाई है कि किस देश से उनको हथियार मिल रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इस विशिष्ट घटना का संबंध है, जिस हथियार का प्रयोग किया गया था उसकी पहचान कर ली गई है कि वह फ्रांस का बना हुआ एक विशिष्ट किस्म का हथियार था। उस हथियार की जांच करने के बाद यह जानकारी दी गई है। परन्तु यह पता नहीं लग पाया है कि उनको यह हथियार किसके द्वारा दिया गया।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या फ्रांस को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ? **(अन्तर्बाधा)**

Dr. Ram Manohar Lohia : The answer has not come. Why France Government has not been asked ?

Mr. Speaker : He says that the exact source has not been established.

श्री स्वैल : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अभी कहा है कि वह श्री हेम बरुआ द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। क्या सरकार की ऐसी नई नीति है ? क्या विभिन्न देशों में स्थित हमारी सरकार के शिष्ट मण्डलों का कर्त्तव्य नहीं है कि वे देश के हितों की ओर ध्यान दें ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि यह मेरा और विदेशों में स्थित हमारे शिष्टमण्डलों का कर्त्तव्य है कि वे हमें पूरी जानकारी दें और वे हमें पूरी जानकारी देते भी हैं। यदि वास्तव में ऐसी बात हुई हो तो मुझे निश्चय ही जानकारी मिल जाती। अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यह एक विशिष्ट मामला है और गंभीर मामला है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसकी सत्यापन करूंगा। सरकार द्वारा कोई नई नीति अपनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

Facilities to Children of Soldiers

\+

***1310. Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Basumatari :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it has been decided to provide jobs to the children of the soldiers, who laid down their lives, in the Defence, Police and Civil Departments after they complete their education;

(b) if answer to part (a) above be in the affirmative, whether those children will be given preference in recruitment to the Defence Services; and

(c) whether similar facilities had been provided in the past also ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जहां तक रक्षा सिब्बन्दियों का संबंध है ऐसे आदेश नवम्बर 1965 में जारी कर दिए गए थे कि युद्ध में मारे गए अथवा निर्योग्य हुए सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य की पत्नी/पुत्र/पुत्री को, अगर वह अधिकारी हो कामदिलाऊ कार्यालय की साधारण प्रक्रिया की छूट देते हुए किसी प्राप्यरिक्त स्थान पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। पुलिस और असैनिक विभागों के बारे में ऐसे आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। तदपि निदेश विद्यमान् हैं कि उत्तर और दक्षिणी बच्चा बटालियन में भर्ती के लिए, सेवा कर रहे और भूतपूर्व सेवीवर्ग के लड़के और दत्तक लड़के ही अधिकारी होंगे।

(ग) कामदिलाऊ कार्यालय की प्रक्रिया के आश्रय के बिना सशस्त्र सेनाओं के किसी उन सदस्यों की पत्नी/पुत्र/पुत्री/निकट कुटुम्बी को काम दिलाने के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थीं अगर वह दिसम्बर 1964 में जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत, ऐसा काम पाने के अधिकारी हों, कि जो सेवा करते मर जाएं, या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हों, या निर्योग्य हो जाएं, और अपने कुटुम्ब को गंभीर स्थितियों में छोड़ जाएं, अथवा सहायता की आवश्यकता में हों।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Did the Defence Ministry issue directions to the District authorities to obtain list of those soldiers from the Ministry who were killed in action and to give employment to their children and also to forward the information regarding persons provided with employment to the Ministry? Has this work been done?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि वे पात्र हैं, तो उनको रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज कराये बिना ही काम दिया जा सकता है। वास्तव में हमने दिसम्बर, 1964 में हिदायतें जारी की थीं और पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात 2 नवम्बर, 1965 को हमने अलग आदेश भी जारी किये थे। हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों को भी लिखा है कि जहां भी संभव हो, रिक्त स्थानों को जवानों के अर्हताप्राप्त आश्रितों द्वारा भरा जाये। आयुध कारखानों के महानिदेशक को 500 रिक्त स्थान रक्षित रखने के लिये कहा गया है। जवानों के आश्रितों को इन सुविधाओं की जानकारी देने के लिये हमने निश्चय किया है कि समय समय पर आकाशवाणी तथा स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा आदेशों की घोषणा की जानी चाहिये। विभिन्न सैन्य छात्रदलों के अफसरों, अन्य सेवायुक्त अधिकारियों को भी, जिनको हमने नियुक्त किया है, जो विभिन्न सेना मुख्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध हैं, हमने यह सलाह दी है कि इन व्यक्तियों से सम्पर्क रखा जाना चाहिये और उनको रोज़गार संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी जानी चाहिये। हमारे पास आश्रितों की सूचि है, और जहां अर्हता-प्राप्त व्यक्ति होंगे हम उनको सुझाव देंगे कि वे रोज़गार के लिये आवेदन पत्र दें।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Jawans who have been killed, generally belong to very remote areas. The means of communications in those areas are not sufficient. May I know whether Government have received any informations regarding the persons who have been provided employment?

श्री अ० म० थामस : जैसा मैंने बताया है, एन०सी०सी० बहुत बड़ा संगठन है। वास्तव में पूरे देश में उसकी यूनिटें हैं। एन०सी०सी० के बड़े अधिकारियों को इस काम पर लगाया गया है कि वे पता लगाएं कि क्या आश्रितों में से कुछ लोगों को रोज़गार में लगाया जा सकता है?

श्री बसुमतारी : एसा जान पड़ता है कि आश्रितों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या इस बारे में सरकार कोई व्यवस्था करनेका विचार कर रही है?

श्री अ० म० थामस : लड़ाई में मरने वालों के आश्रितों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये व्यवस्था है। यह काम करने के लिये हमारे अधिकारी हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सभा के माननीय सदस्यों की उन अभागे लोगों को सहायता देने में रुचि है। मंत्रालय को भी इस बारे में पूरा ध्यान है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने युद्ध में मरने वाले जवानों के बच्चों को आयुध कारखानों में या अन्य सरकारी कारखानों में प्रशिक्षण देने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है?

श्री अ० म० थामस : हिदायतों के अनुसार उन लोगों की नियुक्ति की जाती है जो सभी शर्तें पूरी करते हैं। परन्तु अब हम सोच रहे हैं कि यदि मरने वालों के आश्रित शिक्षा या आयु सम्बन्धी शर्तें पूरी नहीं करते तो हम उनके पिता की मृत्यु के समय से पांच वर्ष तक की रियायत दे दें ताकि उनको उचित पद उपलब्ध किये जा सकें।

Shri Prakash Vir Shastri : Some organisations had offered help for the education of dependents of the persons killed during the Indo-Pak. conflict. I want to know whether the Defence Ministry has taken advantage of that and if so, the number of children benefitted by that?

श्री अ० म० थामस : जी, हां। हमने कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं से इस बारे में सहायता स्वीकार की है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या हाल में पाकिस्तान के साथ हुये संघर्ष में हताहत लोगों के बच्चों को रोज़गार दिलाया जायगा और इस बारे में गैर-सरकारी उद्योगों से भी सहायता मांगी जायेगी।

श्री अ० म० थामस : एक सामान्य अपील की गई है कि सेना से सेवानिवृत्ति पाने वाले लोगों तथा उनके आश्रितों को उचित पदों पर नियुक्त किया जाये। कई मामलों में बहुत उत्साहजनक काम हुआ है।

Shri Buta Singh : I want to know whether any priority in the matter of admission in Sainik schools would be given to the dependents of those killed during in war?

श्री अ० म० थामस : जी हां, कुछ प्रतिशत स्थान उनके लिये सुरक्षित हैं?

श्री बूटा सिंह : ये सुरक्षित स्थान तो सेवा में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये हैं। मैं जानना चाहता हूं, हताहत लोगों के बच्चों के लिये भी क्या कुछ स्थान सुरक्षित है?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में उनको मिलिटरी स्कूलों, सैनिक स्कूलों और लारेंस स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिये व्यवस्था की गई है।

श्रीमती सावित्री निगम : इन वीर सैनिकों के प्रति हमारा आभार व्यक्त करने का तरीका यह होगा कि उनके सभी बच्चों को उचित प्रकार से रोज़गार दिलाया जाये। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे आश्रितों की संख्या क्या है जिनको रोजगार दिलाया गया है और शिक्षा दी गयी है या भूमि बांटी गयी है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। ऐसे बच्चों को मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों में शिक्षा सम्बधी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाती हैं। मेरा अनुभव है कि कुछ परिवार अपने बच्चों को दूर भेजने को तैयार नहीं होते। यदि वे सैनिक स्कूलों या मिलिट्री स्कूलों में अपने बच्चे भेजें तो उनके लिये हमने स्थान सुरक्षित कर दिये हैं। इस समय लगभग 100 स्थान हैं। परन्तु यदि आवश्यकता हुई तो हम इस संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अभी तक तो 100 स्थानों के लिये भी पर्याप्त मांग नहीं है।

जहां तक प्रशिक्षण की बात है हम इस बारे में की जाने वाली पेशकशों पर विचार कर सकते हैं। परन्तु मुख्य प्रश्न, जैसा कि श्री सिद्धान्ती जी ने कहा है, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने का है। इस बारे में हम डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड का लाभ उठा रहे हैं। यही एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा हम भूतपूर्व सैनिकों या हताहत व्यक्तियों के परिवारों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

राष्ट्रमण्डल

*1311. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया है या छोड़ने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि न किसी देश ने राष्ट्रमंडल को छोड़ने की धमकी दी है और न ही किसी देश ने हाल में राष्ट्रमंडल को छोड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में श्री भागवत झा आजाद द्वारा प्रस्तुत, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल छोड़ने से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तान के आक्रमण के समय कई राष्ट्रमंडलीय देशों, विशेषत: ब्रिटेन का रवैया इतना खराब था कि इस सभा में तथा देश में यह भावना फैल गई थी कि भारत को राष्ट्रमंडल छोड़ देना चाहिये। सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि पाकिस्तानी हमले के समय ब्रिटेन का और वहां के समाचारपत्रों का रवैया बहुत आपत्तिजनक था और सरकार ने इस पर पूरा ध्यान दिया था और अपनी राय व्यक्त की थी। एक चर्चा भी हुई थी जो अभी समाप्त नहीं हुई है। देश में इस बात की जोरदार मांग थी कि भारत राष्ट्रमंडल छोड़ दे परन्तु सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं किया है। देश तभी राष्ट्रमंडल को छोड़ेगा जब सरकार या संसद् ऐसा निर्णय करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान की तुलना में भारत की उपेक्षा की है और भारत के बजाये पाकिस्तान के साथ सहानुभूति दिखाई है। इसको तथा भारत के प्रधान मंत्री के साथ किये गये व्यवहार जब प्रधान मंत्री विल्सन ने उनको हवाई अड्डे पर स्वागत नहीं किया आदि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अभी राष्ट्रमंडल में रहना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा राष्ट्रमंडल में रहना या न रहना बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका हवाई अड्डे के स्वागत से कोई संबंध नहीं है... **(अन्तर्बाधायें)** मैं जानकारी दे रहा हूं। आप इससे स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

ब्रिटेन के शिष्टाचार संबंधी नियमों के अनुसार सामान्यत: प्रधान मंत्री अन्य देश के प्रधान मंत्री के स्वागत के लिये नहीं आते हैं। आप इसे पसन्द करें या न करें, परन्तु यह ऐसी बात नहीं है जिस के आधार पर हम राष्ट्रमंडल छोड़ दे।

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister of External Affairs has said that he is not aware whether some countries have threatened to quit the Commonwealth. May I know whether he is aware that many African countries have threatened to quit Commonwealth on the question of Rhodesia?

श्री स्वर्ण सिंह : तथ्य यह है कि घाना और तंजानिया ने ब्रिटेन से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये थे परन्तु इन देशों ने राष्ट्रमंडल को अभी नहीं छोड़ा है। इनमें से घाना ने फरवरी, 1965 में फिर से सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : इस सभा में हाल में कई बार चर्चा हुई है कि राष्ट्रमंडल के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिये। हमें इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया जाता रहा है, परन्तु अब यह समझा जाने लगा है कि राष्ट्रमंडल को छोड़ देना ही लाभकारी होगा। क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया है और क्या वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रमंडल में रहने में लाभों की अपेक्षा हानियां अधिक हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हम निरन्तर इस बारे में विचार करते रहते हैं और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस से हानि हो रही है तो हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं। परन्तु इस समय मैं नहीं समझता कि राष्ट्रमंडल में रहने से हानियां अधिक हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री एटली और भारत के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड माउंटबेटन के कथित परामर्श से वह गलत सूत्र निकाला कि इस देश के दो राजाध्यक्ष हो, अर्थात् यहा राष्ट्रपति और राष्ट्रमंडल के राज्याध्यक्ष हों तब से भारत को ब्रिटेन से जोड़ने वाले संबंध के कारण भारत और राष्ट्रमंडल के अन्य देश सशक्त होने के स्थान पर कमजोर होते जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ब्रिटेन की महारानी वहां की राजाध्यक्ष है परन्तु राष्ट्रमंडलीय देशों पर उनका किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं है वह केवल राज्याध्यक्ष हैं। भारत के राज्याध्यक्ष हैं केवल हमारे राष्ट्रपति ही हैं। यह हमारे संविधान के अनुसार है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से इस में किसी प्रकार अन्तर नहीं होता है। भारत गणतंत्र ही राष्ट्रमंडल का एकमात्र सदस्य नहीं है और भी गणराज्य देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इस से उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रमंडल के सम्मेलन की अध्यक्षता कर सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : ब्रिटेन की महारानी भी राष्ट्रमंडल की सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करती हैं। जब लागौस में राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता नहीं की थी बल्कि तंजानिया के प्रधान मंत्री ने अध्यक्षता की थी। राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह स्वतंत्र देशों का एक संघ है और वे आपसी समान हितों पर विचार करते हैं। वहां पर उपनिवेशवादी मामलों के बारे में ब्रिटेन पर बहुत दबाव डाला जाता है। वहां पर आर्थिक विषयों में सहयोग के अवसर भी मिलते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सैनिक कर्मचारियों के लिये भूमि का आवंटन

*1312. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई जोन में सैनिक कर्मचारियों को आवंटित करने के लिये कुछ क्षेत्र नियत किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि सैनिकों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भमि का आवंटन करने में असाधारण देरी हो रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री(श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : राजस्थान राज्य के सिवाय सैनिक सेविवर्ग को देने के लिये नहरी क्षेत्र में कोई भूमि क्षेत्र अलग नहीं रखे गए हैं। राज्यस्थान सरकार ने रिपोर्ट दी है कि ऐसे सिपाही को भूमि देने में कोई विलम्ब नहीं है जो नियमों के अनुसार भूमि का अधिकारी हो।

ब्रिटेन की राजनीति में जातिवाद की समस्या

*1313. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश राजनीति में जातिवाद की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में राष्ट्रमंडल के आप्रवासियों के लिये ब्रिटिश राष्ट्री आयोग के सदस्य डा० डी० आर० प्रेम द्वारा 13 जनवरी 1966 को नई दिल्ली में की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समस्या के गंभीर रूप धारण करने से पहले उसे हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या ब्रिटन स्थित भारतीय उच्चायोगने भारत से ब्रिटन जाने वाले लोगों को अपना सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने के लिये राज़ी करने हेतु प्रयत्न किये है;

वैदेशिक-कार्य मंत्री(श्री स्वर्णसिंह) : (क) डाक्टर डी० आर० प्रेम ने जिस विषयपर वक्तव्य दिया है, उसके बारे में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) इसकी पहली ज़िमेदारी ब्रिटिश सरकार पर है। बहरहाल, स्थिति को सुधारने की दृष्टी से लंदन-स्थित हमारा हाई कमिशन ब्रिटीश अधिकारियों के साथ बराबर संपक बनाए रखता है।

(ग) ज़ी हां।

उपग्रहों के माध्यम से टेलिविजन व्यवस्था

*1314. श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अपने टेलिविजनों की श्रृंखला का विस्तार करने के लिये उपग्रहों का प्रयोग करने की सम्भावना पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो, उप ग्रहों के माध्यम से संचार के इस व्यापक क्षेत्रमें यदि कोई प्रगति हुई है, तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Netaji's House in Rangoon

*1315. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to purchase the house in Rangoon in which Netaji Subhash Chandra Bose lived and commanded the Indian National Army with a view to convert the house into a historic monument;

(b) if so, whether any negotiations have been held with the Government of Burma in this connection; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

सांस्कृतिक भाषा के रूप में अंग्रेजी

*1316. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 से राष्ट्रमंडल में सांस्कृतिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाये रखना सभी सदस्य-सरकारों की सरकारी नीति बन गई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक देश ने इस सम्बध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये भारत को ब्रिटन से कितनी सहायता मिली है ?

वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जहां तक भारत सरकार का संबंध है, यह सच नहीं है । सरकार को यह मालूम नहीं है कि राष्ट्रमंडल के किसी अन्य सदस्य ने इस तरह की कोई सरकारी नीति अपनाई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

*1317. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी पत्रिकायें इस समय प्रकाशित की जा रही हैं,

(ख) इन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के क्या उद्देश्य है,

(ग) क्या ये पत्रिकायें मुफ्त दी जाती हैं,

(घ) यदि नहीं, तो ग्राहकों से प्रत्येक पत्रिका का कितना वार्षिक मूल्य लिया जाता है, और

(ङ) क्या इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य पूरा हो गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ) : सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग से छपने वाले पत्रों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6132/66।**] भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों/विभागों के पत्रों के बारे में ऐसी ही जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सिक्किम में कागज की लुगदी की परियोजना

*1318. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम में कागद की लुगदी कि एक परियोजना स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस भारतीय तकनीकी दल ने जो सिक्किम गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यह परियोजना कब चालू की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस सिलसिले में भारत सरकार की ओर से कोई भी दल सिक्किम नहीं गया है। इस दिशा में सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

(ग) यह सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण हो जाने पर और अन्य संगत बातों पर निर्भर करेगा।

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीयों की मृत्यु

*1319. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में नजरबन्द कितने भारतीय भारत वापिस लौटाये जाने से पहले वहां मर गये थे; और

(ख) उन में से प्रत्येक किन परिस्थितियों में मरा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान सरकार ने जो सूचना दी है उसके अनुसार जो भारतीय नज़रबन्द भारत प्रत्यावर्तित होने से पूर्व ही पाकिस्तान में मर गए थे, उनकी संख्या 46 है।

(ख) पाकिस्तान सरकार के अनुसार 45 नज़रबन्दों की मृत्यु पश्चिम पाकिस्तान में वृद्धावस्था और कमज़ोरी के कारण हृदय गति रुक जाने से हुई। एक नज़रबन्द की मृत्यु पूर्व पाकिस्तान में फेंफड़े में क्षयरोग हो जाने के कारण हुई।

मिज़ो पहाड़ियों में अशान्ति के कारण शरणार्थियों का पूर्वी पाकिस्तान में जाना

*1320. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को विरोधी पत्र भेजा है कि मिज़ो पहाड़ियों में अशान्ति तथा वहां पर की जाने वाली भारतीय कार्यवाही के कारण शरणार्थी लोग पूर्वी पाकिस्तान में जा रहे हैं जिस के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि पाकिस्तान को कोई उत्तर भेजा गया है तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): सरकार को रिपोर्टें मिली हैं कि मिज़ो विद्रोहियों के कुछ गिरोह पूर्वी पाकिस्तान में चले गए हैं। सरकार ने पाकिस्तान को बताया था कि इन मिज़ो विद्रोहियों को सामान्य रूप से स्वीकृत अर्थों में शरणार्थी नहीं समझा जा सकता। तदनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे ऐसे मिज़ो लोगों को बंदी बना लें और भारत वापस भेज दें।

चीन द्वारा पाकिस्तान को 10 करोड़ डालर की सहायता

*1321. **श्री च० का० भट्टाचार्य** :
श्री जसवंत मेहता :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान चीन गणराज्य के प्रधान (चैयरमैन) द्वारा पाकिस्तान को दिये गये इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि विश्व बाजार से नकद भुगतान के आधार पर हथियार खरीदने के लिए चीन पाकिस्तान को 10 करोड़ डालर की रकम देने के लिए तैयार है;

(ख) क्या चीन ने रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों से नकद भुगतान के आधार पर तत्काल हथियार प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) क्या इस संदर्भ में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए 10 करोड़ डालर का ऋण दिए जाने की रिपोर्ट सरकार ने देखी है। हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि यह ऋण चीन से हथियार खरीदने के लिए है या विश्व मंडी से खरीदने के लिए ।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वियतनाम

*1322. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन में वियतनाम के बारे में व्यक्त सरकार के विचारों से अमरीकी सरकार असन्तुष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन में वियतनाम के बारे में उल्लिखित बातों पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) वियतनाम के सम्बन्ध में भारत के विचारों के बारे में अमरीकी सरकार का नवीनतम दृष्टिकोण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): इस मंत्रालय की 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट में, वियतनाम पर भारत के विचार प्रकट करते समय भारत की विज्ञापित नीति को ही दोहराया गया है, वियतनाम पर कोई नई नीति प्रतिपादित नहीं की गई है। चूंकि भारत सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली है, इसलिए रिपोर्ट में दिए गए विचारों को स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, हाल ही में जब अमरीकी कार्यनायक विदेश मंत्री से मिलने आए थे तो उन्हें स्थिति समझा दी गई थी।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर

*1323. **श्री इन्द्रजित गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 537 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में बनने वाले रेडियो वाल्वज, 3 रुपए 30 पैसे प्रति वाल्व की प्रकाशित दर से बहुत अधिक मूल्य पर चोर बाज़ार में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वितरक एजेंट नियुक्त/पुनः नियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली के बारे में कोई जांच की जायेगी; और

(ग) क्या कम से कम बड़े शहरों में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के अपने फुटकर प्रदर्शन कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कुछ शिकायतें इस प्रकार की मिली है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स में बने हुए वाल्व छपी हुई कीमतों से अधिक दामों पर बेंचे जा रहे हैं।

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स ने भारत के प्रमुख नगरों में अपने डिस्ट्रीब्युटर नियुक्त किये हैं, जो वाल्वों को सीधे ग्राहकों को या अपने एजेन्टों और विक्रेताओं के द्वारा निश्चित दामों पर बेंचते हैं। नियुक्ति की शर्तों में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई अनियमितता का मामला सामने

लाया जाय तो डिस्ट्रीब्युटरों या विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उपर्युक्त (क) में बताई गई शिकायत के बारे में प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है और उसे और आगे बढ़ाया जायेगा।

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स द्वारा फुटकर बिक्री का शो रूम खड़ा करने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

प्रादेशिक सेना के कर्मचारी

*1324. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों ने पाकिस्तानी तथा चीनी आक्रमणों के दौरान युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था;

(ख) इन्हें राज्यों, केन्द्रीय सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र के असैनिक विभागों में फिर से रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पुनःस्थापन निदेशालय प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों के आवेदन पत्र नहीं ले रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। कुछ प्रादेशिक सेना यूनिटों ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने में सक्रिय भाग लिया था।

(ख) जो व्यक्ति प्रादेशिक सेना में शामिल होते हैं, वह अपना असैनिक कारोबार संभालते हुए प्रादेशिक सेना में अंशकालिक तौर पर लिए जाते हैं। वह गंभीर राष्ट्रीय आपात स्थिति में, और तब भी कम से कम समय के लिए सेवा के समंगीकृत किए जाते हैं। असमंगीकरण पर वह अपने असैनिक कारोबार को लौट जाते हैं। उनके पुनरावास का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित भौगोलिक प्रकाशन

*1325. **श्री बूटा सिंह :**
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री तन सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित अनेक भौगोलिक प्रकाशनों में, उदाहरणार्थ, "वर्ल्ड-एटलस," "स्टेट्स एण्ड इकोनोमी", "एर्डकुन्डौन्टे-रिर्क्ट" (भूगोल शिक्षा) और "पेटेरमन्स ज्योग्रफिक मिटाइलुंगेन" (पीटरमेन की भौगोलिक सूचना) में पेकिंग के दावे के अनुसार भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों को साम्यवादी चीन का भाग दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में इन प्रकाशनों की प्रतियां निर्बाध रूप से बांटी जा रही हैं;

(ग) क्या इसके बारे में पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों से विरोध प्रकट किया गया है, और इस संबंध में उनकी कोई प्रतिक्रिया है तो वह क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्रकाशनों को जब्त करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। "वर्ल्ड-एटलस, स्टेट्स एंड इकोनोमी" नामक एटलस के अनुसार चीन-भारत सीमा, जैसी कि वह इसके नक्शे में दिखाई गई है, टूटी हुई रेखा से अंकित है तथा प्रथम भाग के अनुरूप नहीं है और इस पर यह संकेत-वाक्य अंकित है :—

"सीमा का अंतिम रेखांकन चीन लोक गणराज्य और भारत के बीच बातचीत के जरिए स्पष्ट किया जाएगा"

अन्य दो प्रकाशन इस समय सुलभ नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान विनियमों के अनुसार, इन प्रकाशनों के आयात पर और इसी तरह के अन्य प्रकाशनों के आयात पर प्रतिबंध है।

Working of Indian Missions Abroad

***1326. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri B. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of truth in the allegations against the Indian Ambassadors in foreign countries that they generally become accustomed to life of luxury, false sense of prestige and slackness in the performance of their diplomatic duties;

(b) whether Government propose to introduce some measures to improve the working of the Indian Embassies abroad and to appoint most suitable and efficient persons to these posts in the context of the above allegations made generally by all those Indians who visit foreign countries; and

(c) whether any proposal is under consideration to constitute a high level Committee which may, after collecting the relevant facts, suggest means and measures to improve the working of, gear-up the machinery or reorganise the Indian Embassies in foreign countries?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) There is no truth in the allegation.

(b) & (c). A committee has been set up under the Chairmanship of Shri N.R. Pillai to make recommendations for improving the efficiency and effectiveness of Indian Foreign Service in general. It will also suggest measures to improve the working of Indian Missions abroad. The Committee's report is expected shortly.

आत्म-निर्णय का सिद्धान्त

***1327. श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल नरेश की हाल की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि आत्म-निर्णय का सिद्धांत प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों के अभिन्न भागों पर लागू नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोषणा का तिब्बती लोगों की "मूलभूत स्वतंत्रता" तथा स्वतंत्र पखतून आन्दोलन का समर्थन करने के भारतीय दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह घोषणा तिब्बत और पखतूनिस्तान के मामलों पर भारत सरकार की नीति के प्रतिकूल नहीं है।

टेलीविजन सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन

*1328. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सम्बन्धी चन्दा समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : चन्दा समिति की अन्तिम रिपोर्ट 18 अप्रैल, 1966 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

विदेशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*1329. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को परिपत्र द्वारा कहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार को निष्फल करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये;

(ख) यदि हां, तो यथार्थ में क्या हिदायतें जारी की गई है; और

(ग) ये हिदायतें किन परिस्थितियों में जारी की गई थीं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : विदेश-स्थित अपने मिशनों को समय-समय पर निदेश भेजे जाते रहते हैं, जिनमें भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए नीति और प्रचार-संबंधी निर्देश भी शामिल हैं। लेकिन, ये निर्देश ठीक-ठीक क्या होते हैं और किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं, इस पर विचार-विमर्श करना सार्वजनिक हित में न होगा।

दिल्ली छावनी क्षेत्र

*1330. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री हुकम चन्द कच्छवाय : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 9 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) द्वारा की गई इन सिफारिशों के बारे में कि सरकार प्रजातंत्रीय व्यवस्था को संविहित रूप देने के लिए आवश्यक विधान पुर:स्थापित करेगी, अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में आग्रेतर विधान तैयार होने तक क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कि छावनी बोर्डों में प्रजातंत्रीय ढंग में काम होता रहे, कोई कार्यपालिका आदेश/अनुदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं;

(घ) यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अब तक जारी किये गये कार्य पालिका आदेशों का सभी छावनियों में सतर्कतापूर्वक अनुसरण किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कौन-कौन सी ऐसी छावनियां हैं जिनमें ऐसा नहीं किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों को संविधानिक प्रभाव देने के लिए छावनी अधिनियम 1924 के व्यापक संशोधनों से संबंधित कार्य हस्तगत किया गया था। संशोधन कुछ उलझी किस्म के हैं जिसके लिए अन्य नगरपालिका नियमों के सविस्तर और नियमित अध्ययन की आवश्यकता है। इस संबंध में काफी प्रगति हुई है, परन्तु आगे का कार्य वर्तमान आपात स्थिति के कारण स्थापित कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सैनिक स्टेशनों के तौर पर छावनियों के स्वरूप के अनुरूप छावनी बोर्डों में असैनिक जनसंख्या को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। छावनी अधिनियम 1962 के संशोधनों के विषय में व्यापक कानूनसाज़ी की अन्तिम रूपरेखा तैयार होने तक यह आवश्यक नहीं समझा गया कि छावनी बोर्डों के काम करने में और अधिक जनतंत्रता पुरस्थापित करने के लिए कोई आदेश/निदेश जारी किए जाएं।

(ङ) कार्यवाही आदेशों का छावनियों द्वारा पूरी तरह पालन हो रहा है।

भारतीय समाचारपत्रों के बारे में पाकिस्तान का आरोप

*1331. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् को भेजे गये एक पत्र में यह आरोप लगाया है कि ताशकन्द समझौते की शर्तों के प्रतिकूल भारत के समाचारपत्रों ने पाकिस्तान के विरुद्ध उत्तेजनात्मक प्रचार करना फिर से आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :(क) जी, हां।

(ख) ताशकंद घोषणा को क्रियान्वित करने की भारत की सतत इच्छा कई अवसरों पर व्यक्त की जा चुकी है और सर्वविदित है। ये पाकिस्तानी समाचार-पत्र और समाचार एजेंसियां ही हैं जो उत्तेजनात्मक वक्तव्य और टिप्पणियां प्रकाशित करती रही हैं जबकि भारतीय समाचार-पत्रों ने कुल मिलाकर बहुत संयम और मर्यादा से काम लिया है। चूंकि दोनों ही देश ताशकंद घोषणा से बंधे हैं, इसलिए भारत सरकार यह आशा करती है कि पाकिस्तान सरकार इस बात का सुनिश्चिय करेगी कि पाकिस्तान के समाचार-पत्र इसकी व्यवस्थाओं का सम्मान करें।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन संग्रह

*1332. **श्री मधु लिमये :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए किये गये धन संग्रह की ओर दिलाया गया है जिसमें से 1.5 करोड़ रुपये की राशि राज्य में एक ट्रस्ट के रूप में पुलिस बल के लिय निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार धनराशि का आवंटन वैध है और इस कार्य के लिये केन्द्र द्वारा अधिकार दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) मुख्य मंत्री सुरक्षा उद्देश्य कोष (Chief Minister's Defence Purposes Fund) के लिये इकट्ठी की गयी रक़म में से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 1.5 करोड़ रुपये का एक ट्रस्ट क़ायम किया है। इस ट्रस्ट का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सैनिक सहायता संस्थान है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की कार्यकारिणी समिति ने इस पर विचार किया था। उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा इस ट्रस्ट की स्थापना का अनुमोदन नहीं किया। परन्तु जो व्यवस्था की जा चुकी थी, उसको बदलना उचित नहीं समझा गया, इसलिये कि ट्रस्ट पहले से कायम हो चुका था और उसके उद्देश्य लगभग वही थे जो राष्ट्रीय रक्षा कोष के हैं।

सशस्त्र सेनाओं में कनिष्ठ कर्मचारी

*1333. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये एक फोरम (संस्था) बनाने की योजना विचाराधीन थी;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मेरे विचार में प्रश्न सशस्त्र सेनाओं के असैनिक सेविवर्ग के संबंध में है। संयुक्त मंत्रणा और अनिवार्य मध्यस्थता योजना की अन्तिम रूपरेखा तय होने तक, सशस्त्र सेनाओं के जूनियर असैनिक सेविवर्ग की शिकायतें दूर करने के लिए हम एक संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे थे। उस संयुक्त मंत्रणा और अनिवार्य मध्यस्थता योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, और सशस्त्र सेनाओं के असैनिकों के लिए उस योजना का हम अनुसरण करेंगे।

(ख) तथा (ग) उस योजना का मुख्य स्वरूप गृहमंत्री ने लोक सभा में 20 अप्रैल 1966 को बताया है। इसे कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र ही पग उठाए जाएंगे।

"इण्डियन रेयर अर्थज लिमिटेड"

4299. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेयर अर्थज़ लिमिटेड एलूर केरल का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सन् 1962 में इण्डियन रेयर अर्थज़ के आल्वे संयंत्र की क्षमता दुगनी की गई थी। यद्यपि इस समय इसका और विस्तार करने की कोई योजना नहीं है तथापि इसकी उत्पादन क्रियाओं में परिवर्तन के लिए एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। अभी हाल ही में कम्पनी ने बिना विदेशी मुद्रा व्यय किय रेयर अर्थस् फ्लोराइड बनाने वाले संयंत्र का डिजाइन तैयार किया और उसे स्थापित किया। इसके अतिरिक्त लैंथनम आक्साइड बनाने तथा यूरोपियम आक्साइड अलग करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय प्रेस परिषद्

4300. **श्री बसुमतारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना की जा चुकी है,

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक बना दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) भारतीय प्रेस परिषद् स्थापित की जा रही है और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, इसके सदस्यों को मनोनीत करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आकाशवाणी, जयपुर के कलाकारों को वेतन

4301. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में आकाशवाणी, जयपुर (राजस्थान) के स्टाफ कलाकारों को वेतन के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई,

(ख) क्या उक्त अवधि में उन कलाकारों को कोई विशेष भत्ते भी दिये गये थे, और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) फ़ीस के रूप में दिया गया धन :— 1,37,759 रुपये स्टाफ आर्टिस्टों को वेतन नहीं दिया जाता बल्कि फीस तथा भत्ते दिए जाते हैं।

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को अब वही भत्ते दिये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार के असनिक कर्मचारियों को मिलते हैं।

(ग)

महंगाई भत्ता	46,596
नगर भत्ता	5,714
मकान किराया भत्ता	12,501

आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र के आर्टिस्ट

4302. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी जयपुर केन्द्र (राजस्थान) में इस समय कितने स्टाफ आर्टिस्ट तथा अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, और

(ख) उनमें से अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के, अलग अलग, कितने कर्मचारी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) :

स्टाफ आर्टिस्ट	52
अन्य कर्मचारी	136

(ख) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ आर्टिस्ट	8	—
अन्य कर्मचारी	21	9

हैदराबाद तथा विजयवाड़ा आकाशवाणी केन्द्रों के आर्टिस्ट

4303. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा विजयवाड़ा आकाशवाणी केन्द्रों के स्टाफ आर्टिस्टों को वेतन के रूप में, अलग अलग कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या उक्त अवधि में इन आर्टिस्टों को कोई विशेष भत्ता भी दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) फीस के रूप में दिया गया धन:—

हैदराबाद	विजय वाड़ा
रुपये	रुपये
2,29,105	1,42,876

स्टाफ आर्टिस्टों को वेतन नहीं दिया जाता बल्कि फ़ीस तथा भत्ते दिये जाते हैं।

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को अब वही भत्ते दिये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों को मिलते हैं।

	हैदराबाद रुपये	विजय वाड़ा रुपये
(ग). महंगाई भत्ता	53,297	41,840
मकान किराया भत्ता . .	20,964	6,271
नगर भत्ता	1,827	—
बाल शिक्षा भत्ता	—	1,311

आकाशवाणी के आर्टिस्ट, आन्ध्र प्रदेश

4304. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद, विजयवाड़ा, कुद्दाप्पा तथा विशाखापत्तनम स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में इस समय अलग-अलग कितने स्टाफ आर्टिस्ट तथा अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में अलग-अलग, उनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) :

आकाशवाणी केन्द्र का नाम	स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या	अन्य कर्मचारियों की संख्या
हैदराबाद	71	148
विजयवाड़ा	46	118
कुद्दाप्पा	2	42
विशाखापत्तनम	1	42

(ख) आकाशवाणी केन्द्र का नाम :

	स्टाफ आर्टिस्ट		अन्य कर्मचारी	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
हैदराबाद . . .	2	—	26	2
विजयवाड़ा . . .	—	—	19	7
कुद्दाप्पा . . .	—	—	10	1
विशाखापत्तनम . .	—	—	6	1

राजस्थान में सामुदायिक रेडियो सेट्स

4305. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सामुदायिक रेडियो सेट्स दिये गये हैं और राज्य में इस समय कितने रेडियो सेट्स बेकार पड़े हुए हैं, और

(ख) इन रेडियो सेटों की मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) राजस्थान सरकार 1960-61 से पंचायती रेडियो सेट देने की योजना में भाग नहीं ले रही है और उनको तीसरी योजना काल में कोई सेट नहीं दिया गया है। राज्य सरकार स्वयम् अपनी योजना चला रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Children of Stateless Indians in Ceylon

4306. Shri D. N. Tiwary :
Shri A. K. Gopalan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the children of Stateless Indians in Ceylon are refused admission in the schools there; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) & (b). According to Ceylon Government's instructions, all children irrespective of their national status, are entitled to be admitted to schools in Ceylon.

Radio Station at Bhagalpur

4307. Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shrimati Savitri Nigam :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a Radio Station has been commissioned at Bhagalpur; and

(b) if so, the broad details of the programmes to be broadcast from that Station?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):

(a) No, Sir. Work on Auxiliary Centre at Bhagalpur is in progress and the Centre is expected to be commissioned into service during the current year.

(b) As an Auxiliary Centre to the Radio Station at Patna, Bhagalpur will mainly radiate re-recorded programmes supplied by Patna. The programme pattern would, therefore, be identical to that of All India Radio, Patna.

Features on Indo-Pakistan Hostilities

4308. Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether English and Hindi Feature Units had prepared features during the Indo-Pakistan hostilities;

(b) if so, the number of features written during 1965; and

(c) whether these features were relayed from all the Stations of All India Radio?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) English-30; Hindi-92: Total-122.

(c) No Sir. All were not relayed from all the stations.

Construction of Road Near Ghaziabad

4309. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1503 on the 29th November, 1965 and state :

(a) whether there has been any progress in the construction of the road near Ghaziabad; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b): The land required for the construction of the road has been acquired and possession thereof taken over. The work on the construction of the road was started on 14th April, 1966, but was abandoned due to stiff resistance offered by the villagers in regard to the alignment of the road. Efforts are being made to re-start the work.

ब्रिटेन अमरीका और रूस के लिये पारपत्र (पासपोर्ट)

4310. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में ब्रिटेन, अमरीका और रूस के लिये कितने पारपत्र जारी किए गये;

(ख) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने स्वीकार किये गये; और

(ग) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 7134

(ख) 7783

(ग) 57

Republic Day 1966

4311. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the amount spent on the Republic Day Celebrations in January, 1966; and

(b) how it compares with that of the last year?

The Minister of state in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). Information regarding the amount of money spent by the Central Government on Repulic Day Celebrations in January, 1966 is being collected and a statement showing the same will be laid on the Table of the House after the accounts have been finalised. The expenditure incurred by the Central Government on the Republic Day Celebrations held in Delhi in 1965 was approximately Rs. 7,39,700.

Community Radio Sets

4312. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of community radio sets in India at present; and

(b) the number of radio sets actually working?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) 1,41,764 approximately.

(b) 1,06,970 approximately.

Ordnance Factory in U. P.

4313. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to set up an Ordnance Factory in Bulandshahr in Uttar Pradesh;

(b) if so, the estimated cost thereof; and

(c) when its construction is likely to start?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas)

(a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

जाली पासपोर्ट पर गुरदासपुर के श्री देवेन्द्र कुमार की ब्रिटेन की यात्रा

4314. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरदासपुर पंजाब का देवेन्द्रकुमार नामक व्यक्ति जाली पासपोर्ट पर पालम हवाई अड्डे से लंदन गया था;

(ख) क्या पासपोर्ट में उसे ब्रिटिश नागरिक दर्शाया गया था;

(ग) क्या उसके लंदन पहुंचने पर उसके पासपोर्ट के जाली होने का पता चला और उसे भारत लौटा दिया गया;

(घ) जाली पासपोर्ट पर उस को विमान से यात्रा करने देने वाले अधिकारियों तथा यह जाली पासपोर्ट जारी करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : श्री सरवन सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी माडल टाउन, जालंधर, देवेन्दर कुमार पुत्र मोहन लाल के जाली नाम से ब्रिटिश पासपोर्ट पर 30 दिसम्बर, 1965 को पालम से लंदन के लिए रवाना हुए थ। युनाइटड किंगडम के उत्प्रवास अधिकारियों ने यह पासपोर्ट छीन कर अपने अधिकार में ले लिया। इस मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीश कार्य करते हैं

4315. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के लोक सभा के वाद-विवाद के स्तम्भ 124 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में भूतपूर्व उपमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में यह जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि किन-किन समितियों और संविहित निकायों में भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश काम करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मज पर रख दी जायगी।

उड़ीसा के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश

4316. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में उड़ीसा राज्य के समाचार-पत्रों के लिये अखबारी कागज का कितना अभ्यंश नियत किया गया था, और

(ख) क्या 1966-67 में इस अभ्यंश को बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1964-65 और 1965-66 में उड़ीसा राज्य के विभिन्न समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज का जो कोटा नियत किया गया, वह इस प्रकार है :—

1964-65	969.84 मीटरी टन
1965-66	1023.82 मीटरी टन

(ख) चालू साल के लिए अखबारी कागज की वितरण नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी, इसमें इस कोटे में थोड़ी वृद्धि हो सकेगी।

Persons in Foreign Countries Speaking Indian Languages

4317. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons of the Indian origin in foreign countries speaking Indian languages, countrywise, and also the names of those languages;

(b) the steps being taken officially/unofficially to maintain cultural relations between them and India; and

(c) the steps proposed to be taken to promote mutual cultural exchanges?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The approximate number of persons of Indian origin in foreign countries is given in the enclosed statement countrywise. **[Placed in Liberary See No. LT/6133/66]** The number of persons of Indian origin speaking various languages in different countries is not known.

(b) Cultural relations between persons of Indian origin in various countries and India are maintained through the following means:—

Visits of Indian scholars, dance and music troupes, screening of Indian films, maintenance of libraries containing books on India, celebration of Indian National days and festivals, A. I. R. broadcasts in Indian languages etc.

Activities of Institutions like Ramakrishna Mission, Mahabodhi Society, Gandhi Sewak Sangh and Sarvodaya movements also help maintaining close cultural contacts with India. Under the General Cultural Scholarship Scheme students of Indian origin are provided educational facilities in India. The Press and Consular Sections of Indian Missions abroad also maintain relations with persons of Indian origin, and keep them informed about India.

(c) There is a proposal to set up an Indian cultural centre at London. Indian Council of Cultural Relations (under the Ministry of Education) also has some cultural centres in the Caribbean area for the benefit of local Indian population in the area. They also intend to send a Hindi Lecturer to Mauritius and invite some Hindi knowing scholars to India.

नेपाल को सहायता

4318. श्री बसुमतारी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि नेपाल को दी जाने वाली सहायता कम कर दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1961-66 की अवधि के मुकाबले सहायता की राशि काफी ज्यादा होने की संभावना है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना

4319. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना से संबंधित 6 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जांच न्यायालय ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) कोर्ट आफ इन्कवायरी ने निम्न निर्णय दिया है :—

विमान चालक को ठीक ठीक समझाया गया था, और साधारण स्क्वाड्रन प्रशिक्षण के अंश के तौर पर उड़ान लेने के लिए अधिकृत था। उड़ान से पहले वह सा ारण तौर पर स्वस्थ नजर आता था। विमान पूर्णत: सेवायोग्य था, और अन्य विमान चालकों द्वारा नियमित तौर पर उड़ाया गया था। मौसम धुंधला था और दृष्यता 3 वैमानिक मीलों तक सीमित थी, परन्तु स्थिति शांत थी और अन्यथा उड़ान के लिए अच्छी थी। न्यायालय दुर्घटना का ठीक कारण निर्धारित करने में असफल रही। तदापि न्यायालय का विचार है कि दुर्घटना शायद कम से कम अधिकृत ऊंचाई पर विमानचालक द्वारा उड़ान करने के कारण हुई हो। दुर्घटना के लिए सीधे या अन्यथा कोई उत्तरदायी नहीं है ।

जाली पासपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति की गिरफ़तारी

4320. **श्री महेश्वर नायक :**

श्री ॐकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के० सिंह को जो जाली पासपोर्ट बनाता था और एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरदार था, नीदरलण्ड की पुलिस ने रोटरडम में गिरफ्तार कर लिया है और एक सुराग मिला है जिससे पता चला है कि यह गिरोह नैरोबी तथा यूरोप में भी काम करता है; और

(ख) जाली पासपोर्ट बनाने के कितने मामलों का पता इस व्यक्ति के माध्यम से लगा है और प्रभावित व्यक्तियों की किस प्रकार मुआवजा दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) श्री केवल सिंह बैंस और दो अन्य भारतीय राष्ट्रिकों को जिन्होंने जाली ब्रिटिश पासपोर्ट के आधार पर यात्रा की थी, नीदरलैंड की पुलिस ने पकड़ लिया था और दिसंबर 1965 में उन्हें कुछ समय के लिए रोटरडम पुलिस सदरमुक़ाम में रखा गया था। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि नैरोबी में और यरोप में जाली पासपोर्ट वालों का एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है ।

(ख) इस मामले की छानबीन की जा रही है। मुआवज़े का सवाल ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये मलयालम फिल्म

4321. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भेजी जाने वाली फिल्मों में मलयालम फिल्म "चेम्मीन" को शामिल करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) और (ख) : "चेम्मीन" फिल्म विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजने के योग्य पाई गई है और इसको यथा समय समारोह में भेज दिया जायेगा ।

Military Truck Accident on Pathankot-Kangra Road

4322. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Daji :
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the lst April, 1966, ten jawans were killed and one injured in a truck accident near Trilokpur village on Pathankot-Kangra road; and

(b) if so, the causes thereof?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). No, Sir. However, on 30th March, 1966 a 3-ton military lorry fell down in a Khud near Kotla (Pathankot) resulting in the death of four jawans and serious injuries to two jawans. The cause of the accident is not yet known. It will be known as soon as the report of the Military Court of Inquiry appointed to investigate the case becomes available.

राष्ट्रीय रक्षा (नेशनल डिफेंस) कालेज, कनाडा

4323. श्री फिरोडिया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1966 में कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा कालेज का एक दल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) तथा (ख) : नेशनल डिफेंस कालिज कनाडा के निदेशक स्टाफ और छात्र अफसरों पर सम्मिलित 18 सदस्यों के एक दल ने 31 मार्च से 6 अप्रैल 1966 तक भारत का भ्रमण किया था ।

डिफेंस कालेजों के ऐसे दल अपने छात्र अफसरों के दृष्टिकोण को उदार बनाने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न देशों का भ्रमण करते हैं। कनाडा के इस दल ने मुख्यालयों पूर्वीकमान, एक कम्यूनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक, नैशनल डिफेंस कालिज, लोक सभा और भारत एयरोनाटिक्स का भ्रमण किया था। वह उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और सेनाध्यक्ष से भी मिले थे।

आइजल में रेडियो स्टेशन

4324. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ी जिलों में आइजल नामक स्थान में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी और उसकी प्रसारण क्षमता कितनी होगी, और

(ग) इस से किन-किन क्षेत्रों में प्रसारण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र में कम शक्ति का ट्रांसमीटर होगा, जिसके लगाने का खर्चा लगभग 2.45 लाख होगा ।

(ग) अंजल और उससे लगा हुआ क्षेत्र ।

दारेस्सलाम में भारतीय उच्चायुक्त का निवास स्थान

4325. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दारेस्सलाम में भारतीय उच्चायुक्त के निवास के लिये एक बंगला खरीदा गया है;

(ख) यदि हां, तो बंगला किस कीमत पर खरीदा गया है; और

(ग) इसमें उपलब्ध स्थान का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह जायदाद 400,000 शिलिंग (लगभग 266,667 रुपए) में खरीदी गई थी ।

(ग) इसमें निचली मंजिल में एक भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष, अध्ययन कक्ष, अतिथि कक्ष और आनुषंगिक (एन्सिलरीज़) कक्ष हैं और पहली मंजिल में चार शयन कक्ष और विश्राम हाल और आनुषंगिक कक्ष हैं । नौकर-चाकरों के लिए एक मकान है ।

विदेशों में भारतीय मिशनों की देख-रेख

4326. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विदेशों में भारतीय मिशनों में (एक) कर्मचारियों (एस्टेब्लिशमेंट), (दो) भवन की देखभाल तथा (तीन) फर्नीचर पर कितना खर्चा हुआ;

(ख) देश के अन्दर प्रशासन व्यय में जो कमी की जानी है क्या विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रशासन व्यय में भी उसी अनुपात में कमी किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी की जायेगी; और

(घ) उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के रख-रखाव पर जो धनराशि खर्च हुई, वह इस प्रकार है :

(1) निब्बंदी (इस्टेब्लिशमेंट) (भत्तों सहित)

(रुपयों में)

1963-64	3,77,12,097
1964-65	3,88,00,681
1965-66	3,88,58,900

(2) इमारत का रख-रखाव (किराए सहित)

	(रुपयों में)
1963-64	1,11,91,617
1964-65	1,23,28,022
1965-66	1,11,27,400

(3) फर्नीचर (खरीद और मरम्मत)

1963-64 . .	12,57,485
1964-65	13,56,084
1965-66	11,54,700

(ख) जी हां। लेकिन मुख्यालय और विदेश-स्थित हमारे मिशनों—दोनों में प्रभावकारिता को बढ़ाने की हमारी वर्तमान कोशिशों और चीन तथा पाकिस्तान के विरोधी प्रचार का मुकाबला करने की आवश्यकता के कारण इस फैसले के अमल करने पर बड़ा असर पड़ेगा।

(ग) 1966-67 के लिए मिशनों के प्रस्तावित बजट अनुमानों में प्रशासनिक व्यय में किफायत करने की दृष्टि से 5 से 15 प्रतिशत की तदर्थ कमी कर दी गई है। मिशनों को भी हिदायतें दी गई हैं कि वे अमले पर और कार्यालय के रख-रखाव पर खर्च में कमी करें।

Military School at Ghazipur (U.P.)

4327. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether a Military School is proposed to be opened at Ghazipur (Uttar Pradesh);

(b) whether it is a fact that the wife of late Abdul Hamid has made such a request; and

(c) if the reply to part (a) above be in negative, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) No, Sir.

(b) No such request has been received in the Ministry.

(c) There are at present five Military Schools located at Chail (Simla Hills), Ajmer, Bangalore, Belgaum and Dholpur. However, a proposal for setting up a Military School in the Eastern Zone of the country is under consideration in consultation with the State Governments concerned.

छावनी बोर्ड

4328. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 2 दिसम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों में लोकतन्त्रात्मक ढंग से कार्य करने के सम्बन्ध में बार-बार की गई मांग को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने उन पदों को, जो अब तक सैनिक अधिकारियों को नामज़द

करके भरे जाते रहे हैं, असैनिक अधिकारियों को नामजद करके भरने के बारे में जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 13 के अन्तर्गत किया जा सकता है, अपनी नीति में इस बीच परिवर्तन करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बोर्डों में सैनिक अधिकारियों को नामजद करने का औचित्य क्या है, जबकि इन बोर्डों का क्षेत्राधिकार छावनियों के केवल असैनिक क्षेत्रों पर ही होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छावनिएं आवश्यक तौर पर सैनिक स्टेशन हैं। छावनी बोर्डों की नागरिक अधिकार सीमा असैनिक क्षेत्रों सहित समस्त छावनी पर है। सरकार का विचार है कि छावनी बोर्डों के लिए नामित सैनिक अफसरों का रहना छावनी शासन के हित में है। तदपि, वर्तमान् आदेशों के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय श्रेणी छावनियों के छावनी बोर्डों में चुने गए और नामित (पदेन सदस्यों सहित) सदस्यों में समता बनाई रखी जाती है।

दिल्ली छावनी में भूमिगत नाली व्यवस्था

4329. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में भूमिगत नाली व्यवस्था बनाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना में दिल्ली छावनी के सदर बाजार तथा गोपीनाथ बाज़ार के असैनिक क्षेत्र शामिल हैं; और

(घ) इस योजनाकी कार्यान्विति किन कारणों से अभी तक रुकी पड़ी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) : दिल्ली छावनी में मख्य/क्षत्रक स्युअर बिछाने संबंधी, 137.97 लाख रुपये के अनुमानित खर्च की योजना, जिसमें गोपीनाथ बाज़ार और सदर बाज़ार के असैनिक क्षेत्र भी शामिल हैं, सरकार के विचाराधीन है। इस प्रायोजना के लिए 1966-67 के नए बड़े निर्माण कार्यों के कार्यक्रम के लिए, 50,000 रुपये की एक राशि उपबंधित कर दी गई है।

उड़ीसा में आकाशवाणी के द्वारा आदिमजातीय लोक गीतों का प्रसारण

4331. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक, सम्बलपुर तथा जयपुर (उड़ीसा) के आकाशवाणी केन्द्रों से आदिमजातीय लोक गीत तथा उड़ीसा राज्य के आदिमजातीय सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम उचित रूप से प्रसारित नहीं किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेडियो स्टेशन, जयपुर (उड़ीसा)

4332. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट जिले (उड़ीसा) में जयपुर स्थित रेडियो स्टेशन में बहुत कमजोर ट्रांसमिशन उपकरण हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले रेडियो श्रोता कार्यक्रमों को स्पष्टतः नहीं सुन सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। उक्त केन्द्र में विशाखापत्तनम, नागपुर, रामपुर, कालीकट, वाराणसी, धारवाड़, आदि जैसा मध्यम शक्ति का ट्रांसमीटर लगा है और उसके कार्यक्रम जयपुर के इर्द गिर्द के काफी बड़े क्षेत्र में अच्छी तरह सुनाई देते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

जयपुर (उड़ीसा) आकाशवाणी केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट

4333. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट (उड़ीसा) जिले में जयपुर के आकाशवाणी केन्द्र में इस समय कितने स्टाफ आर्टिस्ट काम करते हैं, और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पृथक पृथक कितने स्टाफ आर्टिस्ट हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) :

स्टाफ आर्टिस्ट	1
अन्य कर्मचारी	37

(ख) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ आर्टिस्ट .	—	—
अन्य कर्मचारी .	6	

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाएं

4334. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वाल्वी :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं के बारे में 28 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2925 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि पहले न्यूनतम तथा अधिकतम आयु-सीमाओं में (15 से $17\frac{1}{2}$ वर्ष तक) $2\frac{1}{2}$ वर्ष का ही अन्तर था, संशोधन प्रस्ताव के अन्तर्गत यह अन्तर केवल 2 वर्ष (16 से 18 वर्ष तक) का है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को आधा वर्ष कम करने के क्या कारण हैं; और क्या इस प्रकार इस से एक उम्मीदवार को मिलने वाले अवसर में कमी हो जायेगी;

(ग) क्या मई, 1966 में होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रार्थियों को सीमान्त मामलों में आयु-सीमाओं में कुछ छूट देने की प्रार्थना करने पर कोई छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) : भारतीय रक्षा अकादमी में प्रविष्टि की आयुसीमाओं में संशोधन के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्हें संशोधित करने के अन्तिम निर्णय तक वर्तमान आयु सीमाएं रहेंगी, जो भी निर्णय लिया गया उन लड़कों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने मई 1966 की परीक्षा में बैठने के लिए निवेदनपत्र भेजे हैं। समय समय पर उच्च आयु सीमा में छूट के लिए प्रत्याभिवेदन प्राप्त हुए थे, और उन्हें उचित स्थिति से सूचित कर दिया गया था। चूंकि नियमों में कोई संशोधन न हुआ था, आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रश्न ही न उठता था। ऐसे प्रत्याभिवेदनों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया।

रेडियो सेटों की मांग

4335. **श्री रा० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति 100 व्यक्ति के हिसाब से रेडियो सेटों में कमी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस के कारणों का कोई अनुमान लगाया गया है तथा क्या इस में सुधार करने के लिये कोई उपाय निकाले गय हैं, और

(ग) यूनेस्को द्वारा निर्धारित स्तर की तुलना में यह कमी कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) 1965 में प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे रेडियो सेटों की संख्या 1.11 थी। यूनेस्को का न्यूनतम औसत प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे 5 सेटों का है। जिसका अर्थ है कि भारत में सेटों की वर्तमान संख्या पांच गुनी होनी चाहिए। 1960 में बंगकाक में यूनेस्को की क्षेत्रीय बैठक में यह सिफारिश की गई कि प्रति 5 व्यक्तियों के पीछे एक सेट या लगभग प्रति परिवार के लिए एक सेट का औसत वांछनीय है। इसका मतलब है कि भारत में सेटों की वर्तमान संख्या में लगभग 20 गुनी वृद्धि होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब इसी हिसाब से निर्माण क्षमता बढ़े और रेडियो सेटों के दाम भी घटें, ताकि प्रत्येक परिवार उन्हें खरीद सके।

प्रादेशिक सेना के कर्मचारी (पेंशन सम्बन्धी लाभ)

4336. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना के कुछ अफसरों, जूनियर कमीशन्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों में काम करने वाले सैनिकों ने नियमित सेना तथा भूतपूर्व रियासतों की सेनाओं में की गई सेवा को मिलाकर 15 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को पेंशन अथवा ग्रेच्युटी (उपदान) सम्बन्धी क्या लाभ दिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) प्रादेशिक सेना में समंगीकृत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे मास के वेतन की दर से अधिकाधिक 9 मास के वेतन तक उपदान देय है, अगर व्यक्ति के हिसाब में कम से कम चार वर्ष की समंगीकृत सेवा हो। वर्तमान् नियमों के अन्तर्गत प्रादेशिक सेना में की सेवा के लिए पेन्शन देय नहीं है।

प्रादेशिक सेना में शामिल होने पर नियमित सेना में सेवा के कारण अर्जित पेन्शन और उपदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिवाए इस के कि अफसरों की दशा में समंगीकरण के दौरान या किसी प्रादेशिक सेना यूनिट के स्थायी स्टाफ में सेवा करते समय पेन्शन स्थगित हो जाती है।

प्रादेशिक सेना के अधिकारी

4337. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के किसी अफसर को प्रादेशिक सेना की यूनिटों की कमान सम्भालने के लिए उपयुक्त समझा गया है;

(ख) क्या उन्हें प्रादेशिक सेना निदेशालय में भी नियुक्त करने के लिये उपयुक्त समझा गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने अफसरों को और किन-किन रैंकों में ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। गए समय में ले० कर्नल पद के चार प्रादेशिक सेना अफसरों ने प्रादेशिक सेना यूनिटों की कमान की थी। इस समय 3 मेजर और 4 कैप्टेन छोटी प्रादेशिक सेना यूनिटों की कमान कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रादेशिक सेना का मेजर पद का एक अफसर प्रादेशिक सेना निदेशालय में दूसरे ग्रेड की स्टाफ नियुक्ति पर है। दो अफसर ले० कर्नल पद में कमान मुख्यालयों में स्टाफ नियुक्तियों पर हैं, और 7 अन्य मेजर और एक कैप्टेन निम्न विरचना मुख्यालयों में।

इजराइल के राष्ट्रपति के साथ कथित अशिष्टता

4338. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री इजराइल के राष्ट्रपति के साथ कथित अशिष्टता के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षी सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में कितने विद्रोही प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या उन पर अभियोग चलाया जा रहा है; और

(ग) अभियोग संबंधी कार्यवाही किस अवस्था में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) दफा 144 तोड़ने पर कलकत्ता में 11 अरब छात्र पकड़ गए थ और बाद में ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले की अगली सुनवाई इसी सप्ताह में होनी है।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

23 अप्रेल 1966 को तिनसुकिया—न्यु जलपाईगुड़ी सवारी गाड़ी में विस्फोट

अध्यक्ष महोदय : मुझे रेल दुर्घटनाओं के बारे में 13 स्थगन प्रस्ताव तथा 27 अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मुझे यह भी सूचना मिली है कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य देने वाले हैं। इस लिये पहले वक्तव्य सुन लें और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव को लें।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : 23 अप्रैल, 1966 को सायंकाल को 20 डाउन तिन-सुकिया—न्यू जलपाईगुड़ी सवारी गाड़ी डीफू स्टेशन (लमडिंग से 32 किलोमीटर दूर) पर रात को 8.50 बजे पहुंची। इसके तुरन्त बाद 8.57 बजे एक डिब्बे में वैसा ही विस्फोट हुआ जैसा कि 20 अप्रैल, 1966 को लमडिंग स्टेशन पर हुआ था। इस विस्फोट के कारण 33 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गय और अन्य सात व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हो गई। इनके अलावा 80 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

स्थानीय डाक्टरों ने तुरन्त घायलों की देख भाल की।

प्राथमिक-उपचार के बाद 21 घायल व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस समय जो 59 घायल व्यक्ति अस्पताल में हैं उनमें से 19 को सख्त चोटें आयीं हैं।

सैनिक अधिकारियों ने एक नागा को पकड़ा है जो सन्देहजनक स्थिति में घूमता हुआ पाया गया था।

प्रसादत: अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है। निकट सम्बन्धियों को तार भेजने, नि:शुल्क पास जारी करने, आदि सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री मौके पर मौजूद हैं। और इसके बारे में पूछ ताछ कर रहे हैं। उनसे मिली एक सूचना के अनुसार दुर्घटना में प्रयोग किये गये बम बहुत अधिक शक्ति वाले हैं और शायद विदेशों में बने हैं। यह स्पष्ट रूप से सुसंगठित तोड़-फोड़ का मामला दिखाई देता है। अभी तक लमडिंग तथा डीफू में केवल दो गिरफ्तारियां की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव सदन की अनुमति ले सकते है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want leave of the House to move my adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : जो इसका समर्थन करते हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। केवल 46 सदस्य खड़े हुए है। इसके लिये अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : क्या सरकार स्वयं इसके बारे में कुछ करने को तयार नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा प्रसार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर चर्चा आरंभ करने को तैयार है । समय आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आज सायं 4 बजे इस पर चर्चा होगी ।

सभा पटल पर रखे पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाये

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 486 जो दिनांक 31 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी० एस० आर० 527 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6129/66]**

इंडियन टेलिफोन ईडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर की 1964–65 के लिये वार्षिक रिपोर्ट

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6130/66 ।]**

पंजाब सीमा आयोग के बारे में सरकारी संकल्प

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : श्री नन्दा की ओर से मैं दिनांक 23 अप्रैल, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 17/7/66-एस० आर० की एक प्रति, जिसके द्वारा पंजाब सीमा आयोग, गठित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6/3/66 ।]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ एकवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ एकवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

एकतीसवां प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की मिश्र इस्पात परियोजना तथा कोयला धोने के कारखानों संबंधी परियोजना के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

पंजाब सीमा आयोग तथा भारत रक्षा नियमों सम्बन्धी संकल्प के बारें में

RE: RESOLUTION ON PUNJAB BOUNDARY COMMISSION AND DEFENCE OF INDIA RULES

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये इस पर कुछ कहना चाहते थे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You have so many times ruled that when the Lok Sabha is in Session, all important statements should be made first in Lok Sabha. But that is not being adhered to. The announcement regarding appointment of Punjab Boundary Commission was not first made in Lok Sabha.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : जहां तक इस आयोग की नियुक्ति का सम्बन्ध है, हम ने वही किया है जिसका मूल वक्तव्य में उल्लेख था । केवल पहले किये गये निर्णय को केवल क्रियान्वित किया गया है । इसका निर्णय 23 तारीख को किया गया था और आज उसके पश्चात् पहला दिन है । इसलिये इसकी हम घोषणा कर रहे हैं ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं कें बारें में

RE: CALLING ATTENTION NOTICES

आपात कालीन स्थिति को समाप्त करने तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजर बन्दो को रिहा किया जाना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में दी गई हमारी ध्यान दिलाने वाली सूचना को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको प्रतिदिन निवेदन करता रहा हूं कि आपात कालीन स्थिति को समाप्त करने तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की रिहाई के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं आश्वासन देता हूं कि दो या तीन दिन में इसके ऊपर वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह तथ्य है कि उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह सूचना पहले ही दे दी है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह ठीक है कि कांग्रेस दल अपने दल की बैठक में कोई भी निर्णय ले सकता है परन्तु हमें आपत्ति इस बात पर है कि इन निर्णयों का जनता में प्रचार किया जाता है और बाद में संसद में लाया जाता है । यह उचित नहीं है । इस से इस सभा का मान घटता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 24 अप्रैल के "टाईम्स आफ इंडिया" में यह समाचार छपा है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही भारत प्रतिरक्षा के नियमों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगावेगी । यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने कहा है कि 30 व्यक्तियों के वारंट भी रद्द किये जायें । म चाहता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दें ।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, the important decision are taken by the Ministers at the back of Parliament and they are given publicity in the press and on the air. The members of Parliament are defined of the information. Therefore to illicit information we have to resort to calling attention notices. If this is rejected, we have no other way to know things. We want your protection.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : कांग्रेस दल अपने राजनैतिक प्रचार के लिये समाचार पत्रों को सरकार की नीति के बारे में पहले सूचना दे देती है। आपने भी कई बार इस सभा में कहा है कि नीति सम्बन्धी वक्तव्यों को पहले सदन में दिया जावे और उसके पश्चात् अन्यत्र किसी स्थान पर । परन्तु इसका पालन नहीं किया जाता है ।

अब हमारे सामने ध्यान दिलानेवाली सूचना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : कहा गया है कि कांग्रेस दल के सदस्य समाचार-पत्रों को पहले ही सूचना दे देते हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि विरोधी दल के सदस्य समाचार पत्र वालों से अधिक जानकारी देते हैं । ..... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री सत्य नारायण सिंह : सरकार ने इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है । आज ही हम कैबिनेट की बैठक पर चर्चा कर रहे थे परन्तु किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं । कोई बात समाचार-पत्रों में आ जावे तो इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार ने निणय ले लिया है । मैं अब कहना चाहता हूं कि इस पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। यदि हमने इस मामले को अपने दल की कार्य कारिणी दल के सदस्यों से चर्चा की है तो क्या खराबी की है ?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यदि सत्तारूढ़ दल यह प्रभाव बैठाना चाहता है कि इस देश में एक दल का राज्य है तो यह बहुत खतरनाक बात है । हम इसी बात के विरुध्द आपत्ती उठा रहे हैं न कि इस बात पर कि उनके दल की बैठक में क्या होता है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Sir, I want to say that when Lok Sabha is in session, all policy decisions of the government should be made first here. This appear first in newspapers and air and they have reduced Lok Sabha to the states of a rubber stamp.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी निर्णय दे चुका हूं और आज भी उस पर अड़ा हुआ हूं कि सरकार अपने दल की बैठक में जिस पर चाहे चर्चा करे परन्तु यदि वह सूचना समाचार-पत्रों को दी जाती है तो फिर सदन को यह सूचना पहले मिलनी चाहिये । यदि ठीक बात है और आज भी हमारी स्थिति यही है । सदन के नेता ने आश्वासन दिया है कि इस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्रीमान् जी, वह सदस्य जो बन्दी हैं वह अपना मत किस प्रकार देंगे । इस में क्या हर्ज है यदि सरकार उन्हें यहां ले आवे । उच्चतम न्यायालय उन्हें यहां ला सकता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : महोदय, आपने कहा था कि आप इसके बारे में राज्यों से सूचना प्राप्त करेंगे । मेरी सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल विधान सभा में जो सदस्य बन्दी हैं वह डाक द्वारा मत दे सकते हैं । क्या आपके दफ़्तर ने भी इस बारे में कोई सूचना प्राप्त की है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि बंगाल में ऐसा है परन्तु मैंने संवैधानिक स्थिति को पढ़ा है और मुझ यह कहना पड़ता है कि इसे हम यहां लागू नहीं कर सकते । यहां तो केवल वह सदस्य ही मत दे सकते हैं जो यहां लाये जा सकते हैं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया था । इस मंत्रालय के कार्य के बारे में अच्छे अच्छे सुझाव देने के लिये एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिये । हमारा विदेशों में प्रचार कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । मैं आशा करता हूं इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा । इस मामले में नियुक्त ी गई समिति पर्याप्त नहीं है ।

जालन्धर रेडियो स्टेशन को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये ताकि पाकिस्तान में प्रचार और प्रसार कार्य किया जा सके । पाकिस्तान अपने रवैये के कारण कभी भी भारत का मित्र नहीं हो सकता । भारत के प्रति आशंका तथा घृणा के अतिरिक्त इस के पास और कुछ नहीं है । इसलिये भारत की जनता तथा सरकार का यह काम है कि वे पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले प्रगतिशील तत्वों से भाई चारा बढ़ायें । रावलपिंडी के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिये पूर्वी पाकिस्तान तथा पख्तूनिस्तान में लड़ने वाले लोगों के प्रति हमें सहानुभूति दिखानी चाहिये ।

अमरीका का वर्तमान रवैया भारत की वर्तमान कठिन स्थिति से लाभ उठाने का है । हमें उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि हमें अनाज की आवश्यकता है परन्तु इसके लिये हम अपने सम्मान का सौदा नहीं कर सकते । उर्वरक करार पर ध्यानपूर्वक ध्यान किया जाना चाहिये ।

हमें अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रति वास्तविकता का रवैया अपनाना चाहिये और समाजवादी दे ों से अपने सम्बन्ध और घनिष्ट करने चाहिये । भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय अमरीका और ब्रिटेन के आपत्तिजनक खैये के अतिरिक्त एक और देश अर्थात संघीय जर्मन गणराज्य ने हमारे देश के प्रति शत्रुता दिखाई है । हमें जर्मन लोकतंत्र के प्रति अपने रुख में परिवर्तन करना चाहिये ।

म सरकार से अपील करता हूं कि समाजवादी देशों से अपने सम्बन्ध और सुदृढ़ करे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : प्रधान मंत्री ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य आरंभ किया है । मैं उन्हें इसके लिये बधाई देता हूं । मैंने उनके वक्तव्यों तथा भाषणों को बड़े ध्यान से पढ़ा है । मुझे प्रसन्नता है कि उनमें आत्म-सम्मान की झलक मिलती है । प्रधान मंत्री ने विदेश में भीख नहीं मांगी बल्कि गलतफहमियों को दूर किया है । इस प्रकार उन्होंने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट किया है । प्रधान मंत्री ने वहां पर स्पष्ट किया भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और विश्व शान्ति का सबसे बड़ा समर्थक है ।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा काफी सफल रही है, उन्होंने अपना यह कार्य सम्मानपूर्वक निभाया है । यह भी अच्छा है कि प्रधान मंत्री ने इस आशा को दोहराने के अलावा कि दक्षिण वियतनाम समस्या का न्यायोचित और शान्तिपूर्ण हल होना चाहिये, अमरीकी सरकार को इस बारे में उपदेश देने की

कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई कि दक्षिण वियतनाम के सम्बन्ध में उस की क्या नीति हो, चीन को छोड़कर प्रत्येक विचारशील देश इस बात के लिये चिंतित है कि दक्षिण वियतनाम का संघर्ष एक विश्व संघर्ष का रूप धारण न कर ले। दक्षिण वियतनाम में राजनैतिक अस्थिरता है। दुर्भाग्यवश इस बात के कोई भी लक्षण नहीं हैं कि हनोई विचार-विमर्श के लिये तैयार है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिये चीन हर संभव प्रयत्न करेगा। वैदेशिक कार्य मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि भारत ने इस मामले में वह योगदान नहीं दिया है जो वह दे सकता था। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत रूस को इस बारे में कार्य करने के लिये राजी कर सकता था। एशिया में चीन द्वारा तोड़फोड़ तथा आक्रमण को रोकने के लिये रूसी भी हमारे जितने ही इच्छुक हैं रूस यदि चाहे तो और हमारे आग्रह पर, अपने प्रभाव से, सम्बन्धित पक्षों को बातचीत के लिय राजी कर सकता है और उसके बाद न केवल अमरीकी सेनाएं अपितु उत्तर वियतनाम की नियमित सेनाएं भी हटाई जा सकती हैं। तत्पश्चात शायद युध्द-विराम हो सकता है जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र ने गारन्टी दी है।

यह खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री ने ताशकन्द समझौते का पालन करने का विचार व्यक्त करते हुये यह बात स्पष्ट कर दी कि भारत के लिये अब काश्मीर में जनमत संग्रह करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले के संकल्पों का जो कुछ भी थोड़ा बहुत महत्व हो सकता था वह काश्मीर पर दो आक्रमणों के कारण पूर्णतया समाप्त हो गया है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, ताशकन्द समझौता जानबूझकर लिया गया एक जोखिम था, वह यह कि हमारे द्वारा सामरिक महत्व की दरें एक बार खाली किय जाने पर पाकिस्तान पुनः भारत के प्रति अपनी घृणा नीति अपनायेगा, जैसा कि उसने आज किया है। ताशकन्द समझौते की स्याही सूखने भी न पाई थी कि श्री भुट्टो तथा राष्ट्रपति अय्यूब खां ने पाकिस्तान पंहुचते ही यह घोषणा कर दी कि काश्मीर इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।

ताशकन्द समझौते में पैरा 6 उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें यह कहा गया है कि हम (दोनों देश) आर्थिक तथा व्यापारिक संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पुनःस्थापित करने के उपायों पर विचार करेंगे। भारत ने इस समझौते का पूर्णतया पालन करने का प्रयत्न किया है किन्तु दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इसे क्रियान्वित करने से जानबूझकर इन्कार किया है जिसके लिये चीन से प्रेरणा मिली है और मिल रही है। पाकिस्तान ने केवल भारत को ही नहीं अपितु रूसको भी भ्रम में डाला है। उसने केवल पैरा 2, जिसमें सेनाओं को 5 अगस्त लाइन तक पीछे हटाने की व्यवस्था है की क्रियान्विति की है जिससे उसे हानि की अपेक्षा लाभ कहीं अधिक हुआ है।

चीन नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ताशकन्द घोषणा को क्रियान्वित करे क्योंकि उसका यही प्रयत्न रहा है रूस का एशिया में कोई प्रभाव न हो, वह भारत को भी शक्तिशाली बनने नहीं देना चाहता, हाल में ऐसे समाचार मिले हैं कि चीन कम से कम 150 पाकिस्तानी विमान चालकों को प्रशिक्षित कर रहा है अथवा प्रशिक्षित किय है और पाकिस्तान को उसने कम से कम 80 टैंक भट दिये हैं, चीन और पाकिस्तान के बीच गुटबन्दी स्पष्ट है; हमें इस बारे में किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिये। पाकिस्तान ने नागाओं को सहायता, प्रशिक्षण, हथियार आदि दिये हैं और संभावना ऐसी है कि वह मिजो लोगों को भी इसी प्रकार सहायता करता रहेगा क्योंकि वह ऐसा करने की स्थिति में है।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री विल्सन के दो प्रमाप है, एक श्वेत लोगों के लिये और दूसरा काले लोगों के लिये जो किसी भी बड़े से बड़े प्रतिक्रियावादी टोरी जैसे प्रतिक्रियावादी का है, यह अच्छी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधियों ने रोडेशिया की श्वेत जातिवादी, विद्रोही और अल्प-संख्यक सरकार के विरुद्ध बल के प्रयोग का समर्थन किया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने अपनी प्रथम विदेश यात्रा में जिस बुद्धिमता का परिचय दिया तथा अपने महत्वपूर्ण मिशन में जो सफलता प्राप्त की उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

हम गुटों से अलगाव की नीति में विश्वास करते हैं किन्तु इस का मतलब यह नहीं है कि देश की सभी समस्याएं केवल इसी नीति में विश्वास करने अथवा उसके नारे लगाने से सुलझ सकती हैं। हमारे लिये इस बात की जांच करना आवश्यक है कि आज विश्व किन परिस्थितियों से गुजर रहा है जिनके अन्तर्गत हमें काय करना है। हम आज यह नहीं कह सकते कि विश्व दो गुटों अर्थात, पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों में बंटा हुआ है जिनमें एक का नेता रूस तथा दूसरे का अमरीका है और वे एक दूसरे के समीपवर्ती देशों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि चीन की नीतियों के कारण आज रूस तथा अमरीका एक दूसरे के निकट आ गये हैं। आज ये दोनों देश कई मामलों में, यथा, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाये रखने, आणविक हथियारों के फलाव को रोकने, विश्व में नेतृत्व के सन्तुलन को चीन द्वारा उलटे जाने का भय उसकी युद्ध-पिपासु नीति के संभाव्य परिणाम तथा उसकी विस्तारवादी नीति आदि, के बारे में एक से विचार रखते हैं। विश्व के देशों पर अपना प्रभाव जमाने तथा चीन को अलग रखने के लिये दोनो ही देश प्रयत्नशील हैं, पाकिस्तान हर एक से लाभ उठाने की दृष्टि से चीन, रूस तथा अमरीका तीनों से ही अलग-अलग दोस्ती कर रहा है, रूस तथा अमरीका दोनों ही देश पाकिस्तान को चीन के चंगुल से छुड़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं। रूस को ताशकंद घोषणा से राजनयिक रूप से सबसे अधिक लाभ हुआ है। उसने यह बात सिद्ध की है कि बड़े देशों से वह पहल कर सकता है जिसका दोनों देशों ने, जिनके बीच लड़ाई चल रही थी, स्वागत किया है। उसने चीन और अमरीका को यह दिखा दिया है कि विश्व में उसका राजनयिक प्रभाव बढ़ गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आज विश्व में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में ऐसे देशों का एक तीसरा संसार बना है जो विदेशी प्रभुत्व के अधीन हैं और जिनका संयुक्त राष्ट्र में बहुमत है, रूस और अमरीका में अणुशक्ति की बराबरी तथा शस्त्रास्त्रों में औद्योगिक प्रगति ने अड्डों की आवश्यकता को बेकार कर दिया है।

अमरीका ने पाकिस्तान के साथ उस समय सैनिक समझौता किया था तथा काश्मीर के प्रश्न पर उसका समर्थन किया था जब कि रूस ने भारत का समर्थन किया था। इन दोनों ही देशों को चीन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत के प्रति पाकिस्तान की घृणा की नीति सर्वविदित है। इसलिये यदि पाकिस्तान को सन्तुष्ट करना है तो उसे कुछ न कुछ देना ही होगा जो कि स्वाभाविकत: भारत के लिये हानिकर होगा। ताशकन्द का यही इतिहास है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमें यह अनुभव करना चाहिये कि जब इस सम्बन्ध में रूस ने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की तो निश्चय ही उसका स्पष्ट अर्थ यह था कि उसने यह कह दिया है कि अब उसके विचार दूसरे देश के विचारों के अनुरूप नहीं ह। इसलिय यह साफ जाहिर है कि काश्मीर के बारे में रूस का अब वह पुराना रवैया नहीं रहा, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है।

भारत ने अन्य देशों का समर्थन तथा उन से सहायता प्राप्त की है, किन्तु दास बनकर नहीं, आत्म-सम्मान के साथ। जहां तक ताशकन्द समझौते के भविष्य का सम्बन्ध है, हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि ताशकन्द समझौता पर्याप्त है, हमें पाकिस्तान और चीन के मामले में अभी और पहल लेने के लिये हमें मार्ग ढूंढने है। ताशकन्द समझौता "नो-वार-पैक्ट" नहीं है। यह तो मैत्री सन्धि तक नहीं है। यह तो संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र के अन्तर्गत जिम्मेदारियों को केवल दोहराना है। ये जिम्मेदारियां जिनका अस्तित्व विगत 20 वर्षों से है, पाकिस्तान को भारत पर हमला करने से रोक नहीं सकी। इस समझौते के पश्चात पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कश्मीर को भारत का अंग अब भी नहीं मानता और उसे अब भी काश्मीर आदि में आक्रमण तथा विद्रोह के लिये सहायता करने का अधिकार है। पाकिस्तान सैनिक-शस्त्र तथा प्रशिक्षण द्वारा नागा और मिजो लोगों को सहायता दे रहा है और काश्मीर के अलावा किसी अन्य मामले पर बातचीत करने के लिये वह अब भी राजी नहीं है। अत: ताशकन्द समझौते के पश्चात पाकिस्तान के वर्तमान रवैये को देखकर हमें उक्त समझौते के सन्दर्भ में उसे एकपक्षीय रूप से कई रियायतें नहीं देनी चाहिये।

बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में नई परिस्थितियों के आधार पर हम अपनी विदेशी नीति का पुनर्विलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि नये खतरे का विशेषत: उसका, जो दो बड़े देशों द्वारा अत्यावश्यक सहायता के सभी रास्ते रोकने और अन्य कमजोर राष्ट्रों पर अपने विचार थोपने से उत्पन्न होगा, मुकाबला करने के लिये उसमें पर्याप्त लचीलापन हैं। ऐसे कमजोर देशों की प्रभुसत्ता तथा राज्य क्षेत्रीय अखण्डता को भविष्य में खतरा हो सकता है। इसलिये वास्तविक संघर्ष यह है कि हम अपने अधिकार का दृढ़ता से दावा करें। अत: यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के आधार को सुदृढ़ बनाना है। यदि भारत को स्वतंत्र तथा प्रभावी विदेश नीति अपनानी है तो आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति करना तथा आत्म-निर्भर बनना आवश्यक है और यह भी जरूरी है कि हम पूर्वी तथा पश्चिमी किन्हीं भी देशों पर पूर्णतया निर्भर न करें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सांख्यिकी होने के अतिरिक्त मंत्रालय का प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिये जिसमें उन समस्याओं के प्रति सरकार की नीति की मोटी रूप रेखा का विवरण हो जिनका प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से हम पर पड़ता है। किन्तु हमारी विदेश नीति में हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता प्रतिबिम्बित नहीं होती है। उसमें हमेशा लचीलापन होता है। हमारी विदेश नीति की असफलता इस बात में है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई है, दुर्भाग्यवश हमारी नीति अपने हितों के अनुकूल होने के बजाये अन्य लोगों की खुशी के लिये सदैव परिवर्तनशील रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने ताशकन्द समझौते के बारे में जिसमें एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में जिसमें काश्मीर भी शामिल है, हस्तक्षेप न करने की बात कही गई है, अत्यधिक विश्वास दिखाया है। किन्तु क्या पाकिस्तान ने भी वैसा ही सोचा है ? इसका उत्तर है 'नहीं', पाकिस्तान के अनुसार काश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है। काश्मीर के प्रश्न पर न केवल विश्व की राजधानियों में ही अपितु ताशकन्द और रावलपिंडी जैसे स्थानों में भी विचार करके हमने पाकिस्तानी विचारधारा को माना है, यदि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है—जो तथ्य है, तो फिर सरकार इस पर बार-बार, जहां-कहीं विचार-विमर्श क्यों करती है—इसलिये कि पाकिस्तान ने इसे विवादास्पद राजक्षेत्र की संज्ञा दी है और सरकार को खुद अपने पर यकीन नहीं है।

सितम्बर, 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का विश्व में एक भी मित्र नहीं है। हमारी विदेश नीति से हमें अभी तक यही प्राप्त हुआ है। विश्व के बड़े तथा छोटे देशों ने पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन किया है और हमें कहीं से भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हैरोल्ड विल्सन ने भी पाकिस्तान पर कथित आक्रमण के कारण भारत की निन्दा की है हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया, जब श्री विल्सन ने ऐसा व्यवहार किया, तो ऐसा सन्देह है कि राष्ट्र मंडल के देशों के विचार भी ऐसे ही होंगे। भारत को स्पष्ट रूप से यह बात कह देनी चाहिये कि यदि राष्ट्र मण्डल के वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार पक्षपात पूर्ण व्यवहार करेंगे तो हमारे लिये उसका सदस्य बना रहना असम्भव होगा। आज यह कहना सच है कि ताशकन्द घोषणा धीरे-धीरे असफल हो रही है और उसका कारण है-पाकिस्तान के साथ चीन की सांठगाठ जो अत्यधिक बढ़ती जा रही है, चीन चाहता है कि काश्मीर दूसरा वियतनाम बन जाये और पाकिस्तान उत्तरी वियतनाम जैसा कार्य करे, ये दोनों देश हमारी राजनतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहते है, इन सब कारणों से तथा ऐसी स्थिति में हमारे लिये यह अनिवार्य हो गया है कि हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा न केवल अपनी सैनिक शक्ति बढाकर अपितु एक ऐसी नीति अपनाकर भी करनी चाहिये जिसमें राष्ट्रीय हितों का अत्यधिक ध्यान रखा जाये।

भारत में ऐसे भी लोग हैं जो यह तर्क देते हैं कि ताशकन्द समझौते की भावना के अनुसार चीन के साथ भी एक समझौता किया जाना चाहिये। परन्तु क्या 145,000 वर्गमील का अपना राज्य क्षेत्र देकर, जिस पर चीन ने बलात् कब्जा कर रखा है, हम शान्ति स्थापित कर सकेंगे ? खेद है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि वह चीन के साथ बात-चीत करने के लिये तैयार हैं, समझमें नहीं आता कि वह किन शर्तों के आधार पर चीन से बात चीत करने के लिये तैयार हैं।

[श्री हेम बरुआ]

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हम तिब्बत में मानव अधिकारों की पुनःस्थापना की मांग कर रहे हैं। इस साहसपूर्ण वक्तव्य के लिये सरकार बधाई की पात्र है। किन्तु सरकार को इस से भी एक पग और आगे बढना चाहिये और बदली हुई परिस्थिति में उसे तिब्बत पर चीन के अधिराजत्व को रद्द कर देना चाहिये। यदि चीन काश्मीर के बारे में आत्मनिर्णय की मांग कर सकता है तो भारत तिब्बत के बारे में जहां जनवध करना लगभग कानून का एक अंग बन गया है, क्यों कुछ नहीं कह सकता।

चीन की बढ़ती हुई आणविक शक्ति एक गंभीर चिन्ता का विषय है। मन में अशान्ति पैदा करने वाले ऐसे समाचार मिले हैं कि 1968 में पाकिस्तान अपने बम का विस्फोट करेगा। हो सकता है कि आणविक हथियारों से आज हमें कोई खतरा नहीं किन्तु अपने भविष्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिये।

जहां तक हमारी विदेशा नीति का सम्बन्ध है, यदि वह वास्तव में ही गुटों से अलगाव की नीति है, तो उसके अन्तर्गत किसी एक अथवा अन्य किसी गुट के प्रति कोई भावात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक पक्षपात नहीं करना चाहिये, दुर्भाग्यवश हम दोहरी नीति अपना रहे हैं। इसराइल के राष्ट्रपति के प्रति जो अशिष्टतापूर्ण व्यवहार दिखाया है वह इसका एक उदाहरण है।

मैं नागालैंड के बारे में, समयाभाव के कारण विस्तार में तो नहीं किन्तु संक्षिप्त में दो-एक खास-खास बातें जरूर कहूंगा। 22 मार्च को कोहिमा में गणतंत्र दिवह समारोह के बारे में बोलते हुये वैदेशिक कार्य मंत्री ने कहा कि 22 मार्च नागाओं के लिये कोई विशेष महत्वपूर्ण दिन नहीं है, किन्तु वह गलत वक्तव्य था। 22 मार्च का नागाओं के लिये विशेष महत्व है क्योंकि उस दिन, 22 मार्च, 1956 को स्वतंत्र नागालैंड के लिये नागालैंड का संविधान स्वीकार किया गया था और वास्तव में फेडरल सरकार स्थापित की गई थी।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : हमारी प्राचीन संस्कृति यह बताती है कि हमारी नीति कभी भी स्वार्थ की नहीं रही है। हमें आज भी अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी नीति बनानी चाहिए। हमें सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। यह ठीक है कि हमने अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ गत वर्षों में अपनी मैत्री बढ़ाई है। किन्तु इसके साथ साथ हमारा यह भी कर्तव्य होना चहिये कि यदि उन देशों के साथ कोई अन्याय हो या उन पर विदेशी आक्रमण हो, तो हमें उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए यदि हम सभी देशों के साथ अपनी मैत्री बनाये रखेंगे तो, हमें उस से भले ही आर्थिक लाभ न हो किन्तु हमारी स्थिति विश्व में सुदृढ़ हो जायेगी।

इस उप महाद्वीप में जो भी कठिनाइयां पैदा हुई है वह पाकिस्तान को अमरीका द्वारा बड़े पैमाने पर हथियार दिये जाने के कारण पैदा हुई। चीन ने भी यही सोचा की भारत अमरीका का समर्थक बनेगा। इसीलिये वह हमारे विरुद्ध हो गया। चीन समझता था कि अमरीका की भारत के साथ मिल कर उसपर हमला करेगा। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान को हथियार देते समय अमरीका ने भारत को स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया था कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। किन्तु पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी भारत पर आक्रमण करके हमारे विरुद्ध इन हथियारो का खुले रूप में प्रयोग किया। भारत के प्रति किसी भी पश्चिमी राष्ट्र ने न तो कोई सहानुभूति ही दिखाई और न ही पाकिस्तान की इस कार्यवाही को अनुचित बताया। यदि पूर्वी यूरोप के देश हमारे प्रति सहानुभूति न दिखाते और हमारी सहायता न करते तो हम बहुत बड़ी कठिनाई में फंस जाते। इस कठिनाई के समय रूस ने मिग विमान देकर हमारी सहायता की। अतः हमें अपने मित्रों को भूलना नहीं चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हमे इज़राइल को मान्यता देनी चाहिए इससे हमारे व्यापार में वद्धि होगी। मैं समझता कि हमें इसराइल को मान्यता देकर संयुक्त अरब गण राज्य तथा अन्य अरब देशों से अपनी मित्रता नहीं घटानी चाहिए। अरब देशों के साथ हमारा व्यापार बड़े पैमाने पर चलता है। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें इज़राइल तथा अरब देशों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए।

यह ठीक है कि हमें जर्मन लोकतंत्री गण-राज्य को मान्यता देनी चाहिए। किन्तु यदि वह ऐसे मानचित्र प्रकाशित करे जिनमें पाकिस्तान के सम्बन्ध में काश्मीर को तथा चीन के सम्बन्ध में हमारी स्थिति को इस प्रकार दिखाया गया हो, कि वह हमारे प्रतिकूल हो, तो हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा।

आज चीन के पास सब से बड़ी नौ सेना है। उसके पास 40–50 पनडुब्बियां हैं। हम उससे बहुत पिछड़े हैं किन्तु हमने इस सम्बन्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार गलत है कि हमें चीन के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें बातचीत का मार्ग बन्द नहीं करना चाहिए। चीन से बातचीत करना उचित है। हमें पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। हमें इस कार्य के लिये अपने संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भेजने चाहिए ताकि दोनो देशों का मनमुटाव समाप्त हो सके। यह ठीक है कि पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौते की भावना की उपेक्षा की है किन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि दोनों देशों के ससंद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलों के आदान-प्रदान से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में काफी सहायता मिलेगी।

विश्वभर के पत्रकार-प्रतिनिधि मंडल भारत आये किन्तु रूस, रूमानिया, पोलैंड आदि पूर्व यूरोप के देशों का कोई पत्रकार-प्रतिनिधि मंडल भारत नहीं आया। वे लोग भारत आने के बहुत इच्छुक हैं। अतः इन देशों के पत्रकारों को भारत आने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिए।

ऐसा कहा जाता है विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूत विलास के जीवन के अभ्यस्त हो गये हैं। यह देश के लिये शोभा की बात नहीं है। हमारे राजदूतों को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे देश का सम्मान तथा गौरव बढ़े। उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भारतीय विदेश सेवा समिति में भारतीय भाषा के प्रेमी ही लिये जाने चाहिए। हमें अन्य देशों के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रव्यवहार करना चाहिए।

पिछली बार विदेशों में भेज गये संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलो ने बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया है। अतः मेरा अनुरोध है कि विदेशों में संसद सदस्यों के और अधिक प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने चाहिए।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : आज हम जब अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे है हमारी स्वतंत्रता को खतरा बना हुआ है। अतः हमें वास्तविकता का सामना करने के लिये अपनी विदेशी नीति पर पुर्नविचार करना होगा। हम देख चुके हैं कि कि प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बाद भी अमरीकी सरकार का दृष्टिकोण भारत के प्रति अछा नहीं हैं। यह सभी जानते है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ सनिक समझौता कर लिया है किन्तु फिर भी अमरीका जानबूझ कर उसे सहायता दे रहा है और उसका समर्थन कर रहा है। यदि अमरीका पास्कितान को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता नहीं देता तो वह कभी भी भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करता। पाकिस्तान को सहायता देते समय भारत में अमरीका से विरोध प्रकट किया था और श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अमरीका भेजा गया था। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आइज़न हॉवर ने स्पष्ट शब्दों में श्रीमती पंडित को आश्वासन दिया था कि अमरीका पाकिस्तान को चीन के विरुद्ध सैनिक सहायता दे रहा है और उसका प्रयोग भारत के विरुद नहीं किया जायेगा। किन्तु पाकिस्तान ने अमरीकी हाथीयारों का भारत के विरुध्द खुले रूप से प्रयोग किया। अब पाकिस्तान ने चीन से भी हथियार लेना आरंभ कर दिया है किन्तु अमरीका ने इसके विरुद्ध अब तक एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरी ओर अमेरीका के रक्षा मंत्री श्री मेकनमारा ने अमरीका की सीनेट में विचार व्यक्त किय है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता जारी रखी जाये। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका पाकिस्तान को सहायता चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिये नहीं दी जा रही है।

[श्री नि० चं० चतर्जी]

यदि हम मिजो लोगों अथवा नागाओं द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को अच्छी तरह ध्यान दे तो हमें मालूम होगा कि यह सब हमारी गलत विदेश नीति का परिणाम है। इन कार्यवाहियों के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है। जब तक हम सही विदेश नहीं अपनायेंगे और अपने देश के अन्दर की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी।

हम गुटों से अलग रहने की नीतियों के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु आज हम एक अजीब स्थिति में फंस गये हैं। आज हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के आश्रित होते जा रहे हैं क्योंकि व हमें उर्वरक और अनाज दे रहे हैं। इससे हम में आत्मतुष्टि की भावना पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि हमारी विदेश नीति का नये उपनिवेशद से गठबन्धन हो गया है। हम इसके परिणामों से अनभिज्ञ हैं। क्या आज हम अनाज और उर्वरक के उपहार के बदले में अपनी स्वतन्त्रता बेचने जा रहा हैं। आज हमें बड़ी सावधानी और सतर्कता से काम लेना है ताकि इतने संघर्ष और परिश्रम से प्राप्त की गई स्वतंत्रता कहीं दूसरों के हाथों में न चली जाये। हमारे वर्तमान शासको की आत्मतुष्टि हमें महंगी पड़ेगी। अब भी समय है जब सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में सतर्कता तथा सावधानी से काम लेना चाहिये।

कुछ लोग ताशकन्द समझौतेसे प्रसन्न नहीं है। यह समझौता भारत को बहुत महंगा पड़ा है। इस समझौते ने भारत के महान राजनितिज्ञ तथा महान देशभक्त श्री लालबहादुर शास्त्री का जीवन ही ले लिया। इस से भारत को बहुत अपमान सहना पड़ा है। हमने अपने सैकड़ों सैनिकों का जीवन देकर जिस अपने क्षेत्र को जीता था, वह हमें छोड़ना पड़ा है।

आज भारत में एक भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान खोलने की बात कही जा रही है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम अपना सांस्कृतिक नेतृत्व भी अमरीका के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। आज हम अपनी योजनाएं भी बिना विश्व बैंक की अनुमति के नहीं बना सकते हैं। हम हर बात के लिये विश्व बैंक या अमरीका पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज के संसार में विश्व बैंक ईस्ट इंडिया कम्पनी का काम कर रहा है। हमारी स्वतंत्रता को अनाज, उर्वरक तथा अन्य सहायता के लिए बेचा जा रहा है। यह हमारे लिये अपमान की बात है कि हमारी चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं की रूप रेखा विश्व बैंक द्वारा तैयार की जायेगी। इससे देश पर भारी खतरा आने वाला है। सरकार के लिये अब भी सतर्क होने का समय है।

अब मैं राष्ट्र मंडल के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हमें राष्ट्र मंडल के बारे में अब पुनर्विचार करना चाहिए। आज भारत को राष्ट्र मंडल के सदस्य बने रहने से कोई लाभ नहीं है। श्री विल्सन तथा श्री फैन्नर ब्रॉकवे ने भारत के विरूद्ध खुले रूप में पाकिस्तान का समर्थन किया है और भारत को आक्रमक कहा है। फिर भी ब्रिटेन अपनी ही नीति को उचित बताता है। अब ब्रिटेन में अपने उच्चायुक्त के कार्यालय में इतने अधिक कर्मचारी रखने का कोई लाभ नहीं रह गया है।

यह खेद की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 50 प्राफेसरों और लेक्चररों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच की जायेगी क्योंकि उन्होने हमारे सांस्कृतिक जीवन पर अमरीकी प्रभुत्व का विरोध किया था। ऐसा लगता है कि "मैकाथी वाड" अपने देश अमरीका में तो समाप्त हो चुका है किन्तु अब वह भारत में आकर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का त्याग न करे।

यह देख कर दुख होता है कि कुछ लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी की इसलिये आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चीन से बातचीत आरम्भ करने की बात कही है। जब हम पाकिस्तान से बातचीत कर सकते हैं तो चीन के साथ बातचीत न करने का कोई कारण नहीं है। हमें चीन के साथ बातचीत करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिए। यदि बात चीत असफल हो जाती है तो चीन का पर्दा फाश हो जायेगा।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस का दौरा बहुत लाभदायक रहा है तथा इससे हमारे देश और उन देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है । उनके दौरे से भारत और फ्रांस के सम्बन्ध, विशेषकर सांस्कृतिक क्षेत्र में, और अधिक सुदृढ़ हो जायेंगे और हमें आशा है कि इसके फल-स्वरूप कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारा सहयोग बढ़ेगा ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अमरीकी राष्ट्रपति हमारे शुभचिन्तक हैं, किन्तु उनके दो सलाहकार, श्री डीन रस्क और श्री मैकनमारा, पाकिस्तान के समर्थक हैं और वे भारत के साथ अमरीका की मैत्री कम करने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहते। दूसरी बात यह भी है कि अमरीका ब्रिटन की सलाह पर काम करता है । ब्रिटेन आरंभ से ही पाकिस्तान का दृढ़ समर्थक रहा है । मैं समझता हूं कि यदि अमरीका भारत के मामले में ब्रिटेन से सलाह न लेकर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाए तो यह भारत के लिये बहुत अच्छी बात होगी । राष्ट्रपति जांनसन को इस सम्बन्ध में सावधानी से काम करना चाहिए ।

ताशकन्द समझौता भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए हितकर है । यदि दोनों देश इस समझौते का निष्ठापूर्वक पालन करें तो दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे होंगे और दोनों देशों की अर्थ व्यवस्था समृद्ध होगी । किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान इसका पालन करने के स्थान पर उल्लंघन कर रहा है जब कि हम अपनी ओर से उसका पूर्णतः पालन कर रहे है । हमें इसके बारे में रूस के प्रधान मंत्री को अवगत कराना चाहिए । इस समझौते की क्रियान्विती की देखरेख करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें भारत, पाकिस्तान तथा सोवियत संघ का एक एक प्रतिनिधि हो । हम ताशकन्द समझौते की शर्तों का पाकिस्तान द्वारा पालन किये जाने के बारे में अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं । हम थोड़े समय तक और प्रतीक्षा करे और यदि तब तक पाकस्तान शर्तों का पालन करे तो ठीक है नहीं तो हमारी ओर से भी उसका कोई महत्व नहीं रहना चाहिए ।

गुटों से अलग रहने की हमारी नीति काफी सफल रही है । हम किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं । हमारी यह नीति विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्त के अनुरूप होनी चाहिए । यह नीति इस बात में भेदभाव नहीं रखती कि विश्व के देशों में भेदभाव किया जाये । हमें अपनी नीति के बारे में अन्य देशों को बताना चाहिए और इजराइल, जर्मन लोकतंत्रीय गणतन्त्र तथा अन्य देशों के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहिए ।

यूथोपिया के लोग भारत के घनिष्ट मित्र हैं । सरकार को उनके साथ अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने चाहिए । यह सराहनीय बात है कि हमारे विदेश प्रचार में काफी सुधार हो गया है किन्तु हम अभी तक कुछ देशों को अपनी धर्म निर्पेक्षता के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं दे पाये हैं । हमें इस सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिए ।

स्वर्गीय महात्मा गांधी तथा श्री नेहरू हमारे आदर्शों के प्रतीक हैं । यह सराहनीय बात है कि विश्व के बहुत से देश उनके आदर्शों को अच्छी तरह समझते हैं । अभी हाल में केनिया में नेहरू स्मारक प्रदशनी का आयोजन किया गया था । इस प्रकार की प्रदर्शनियां सभी देशों में आयोजित की जानी चाहिए ।

ब्रिटन अब भी जातिवाद की नीति अपना रहा है । केनियां के स्कूलों में पढ़ाने वाले ब्रिटेन के अध्यापकों ने अपने विद्यार्थियों को केनियां में आयोजित नेहरू स्मारक पदर्शनी में नहीं जाने दिया । इससे हम समझ सकते हैं कि भारत के प्रति ब्रिटेन का कसा रवैया है । हमें अपनी उत्प्रवास सम्बन्धी नीति पर भी पुनर्विचार करना होगा । ब्रिटेन की इस जातिवाद की नीति के बारे में मंत्री महोदय को जांच करनी चाहिए ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश की विदेश नीति बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लचीली बनाई जानी चाहिये। हमारी विदेश नीति 15 वर्ष पहले की परिस्थितियों के लिए चाहे कितनी अच्छी रही हो किन्तु वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। आज समूचे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन हो गया है। हम गुटों से अलग रहने की बात तो करते है किन्तु कुछ देशों के लिये हम कुछ देशों को मान्यता तक नहीं देते हैं। अब गुटों से अलग रहने की नीति का कोई महत्व नहीं रह गया है। अतः गुटों से अलग रहने के पुराने सूत्र को बार बार दोहराने के बजाय हमें वास्तविक दृष्टि कोण अपना कर अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

इसराइल को बने हुए अब लगभग एक पीढ़ी का समय हो चुका है। किन्तु हम उसकी इस कारण उपेक्षा करते जा रहे कि कहीं अरब देश नाराज न हो जायें। वास्तव में हम इसराइल के विरुद्ध गुट के समर्थक रहे हैं। हम हमेशा अरब देशों को प्रसन्न करन का प्रयत्न कर रहे हैं और इसराइल की निन्दा करने में अपना गौरव समझते हैं। भारत में इसराइल के वाणिज्य दूत को दिल्ली में इसराइल का स्वाधीनता दिवस मनाने की जो अनुमति दी गई थी, वह दो वर्ष पूर्व वापिस ले ली गई है। एक माह पूर्व हमने नेपाल जाते हुए इसराइल के राष्ट्रपति के साथ जो अशिष्टता का बर्ताव किया है उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि हम शिष्टता की परिभाषा ही भूल चुके हैं।

इसराइल के राष्ट्रपति ने 1965 में इस देश की यात्रा करने का इरादा किया था परन्तु पाकिस्तान के साथ उस समय हो रहे संघर्ष के कारण इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। नेपाल जाते समय जब उन्होंने इस देश में रुकने का विचार प्रकट किया तो उनको दिल्ली में रात गुजारने की अनुमति नहीं दी गई बल्कि उनको कहा गया कि वह कलकत्ता में रात गुजार सकते हैं। वहां भी हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिये कोई नहीं गया इस प्रकार जब वह नेपाल से वापस दिल्ली में कुछ समय ठहरे तो वहां भी हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिये कोई नहीं गया। इस प्रकार उनके साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार किया गया जिसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता। ऐसा व्यवहार करना हमारे देश की संस्कृति तथा परम्पराओं के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इससे भी अधिक शर्म की बात यह है कि कलकत्ता में हवाई अड्डे पर हमने उनके लिये जो कारों की व्यवस्था की उसके लिये हमने उनको 400 रुपये का बिल भेज दिया। आशा है प्रधान मंत्री इस समूचे मामले के तथ्यों पर विचार करेंगी और यदि वह संतुष्ट हो जायें तो इसराइल गणराज्य के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर खेद व्यक्त करेंगी। मुझे आशा है कि इसके पश्चात वह इसराइल को मान्यता देने तथा उस देश के साथ राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कार्यवाही करेंगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार का विचार है कि यदि इसराइल गणराज्य को मान्यता दे दी गई तो अरब देश अप्रसन्न हो जायेंगे। अरब देशों के एक नेता जो कि एक अरब देश के राष्ट्रपति भी हैं, ने कहा है कि अब समय आ गया है जब कि अरब देशों को इसराइल के प्रति अपने रवैये परिवर्तन करना चाहिये। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान बहुत से अरब देशों ने खुले आम भारत के विरुद्ध शत्रुता दिखाई थी और अब भी बहुत से अरब देश पाकिस्तान नकदी तथा सैनिक सहायता दे रहे हैं। 1950 में जो स्थिति थी अब वह बिल्कुल बदल गई है तथा तथ्यों को देखते हुए इसराइल के प्रति हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। इसराइल के प्रति हम जो नीति अपना रहे हैं वह न तो हमारे जैसे महान देश को शोभा देती है और न ही वह हमारे हितों के अनुकुल हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि भारत ने चीन के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई हुई है। चीन के प्रति एक निश्चित नीति अपनाने की आवश्यकता है। चीन की विस्तारवाद की नीति का पुराने ढंगों से सफलतापूर्वक मकाबला नहीं किया जा सकता। हमारे हितमें यह आवश्यक है कि चीन के साम्यवाद को रोकने के लिये हम यथार्थ नीति अपनायें। आवश्यकता इस बात की है भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देश मिलजुल कर चीन के विस्तारवाद को रोकने का यत्न करें।

श्री अ० कु०सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि देश को जिन समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है वैदेशिक कार्य मंत्रालय को उसकी पूरी जानकारी है तथा वह उसपर गम्भीरता से विचार करता है और उसको प्रत्येक समस्या की गम्भीरता के बारे में पूर्ण जानकारी है । मंत्रालय ने इन समस्याओं को हल करने के लिये जिस साहस तथा निष्पक्षता का सबूत दिया है वह सराहनीय है । कुछ सदस्योंने पश्चिम देशों से तथा कुछ सदस्यों ने पूर्वी देशों से सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के बारे में शंका व्यक्त की है चाहे वह सहयोग तथा सहायता बिना किसी शर्तों के ही क्यों न हों । परन्तु हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रशासन ने मूल तथ्यों को स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि वह दूसरे देशों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं और वह जीवन की मूल बातों, स्वतंत्रता तथा आखण्डता को क्षति पहुंचाये बिना दूसरे देशों से सहायता लेने को तैयार हैं चाहे वह सहायता किसी भी देश से क्यों न मिले । मैं निवेदन करता हूं कि सरकार में इस बारे में पूण विश्वास किया जा सकता है कि चाहे जो भी हो वह हमारे राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा तथा स्वतन्त्रता पर आंच नहीं आने देगी । दूसरे देश भी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हम अपने सम्मान तथा स्वतन्त्रता के बारे में किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है । हम विश्व के दूसरे देशों के साथ सहयोग करने के लिये इच्छुक है परन्तु हम ऐसा सहयोग स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की वदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों के ही विरुद्ध हो । यह कहना गलत है कि सरकार ने अमरीका अथवा अन्य किसी भी देश से सहायता स्वीकार करके देश के सम्मान के बारे में कोई समझौता किया है ।

चीन तथा पाकिस्तान दोनों से हमें खतरा है । इस संयुक्त खतरे का मुकाबला निराशा प्रकट करने से नहीं किया जा सकता । हमने चीन के साथ मित्रता बनाने के लिये सभी प्रयत्न किये परन्तु चीन ने सदा हमे हानि पहुंचाने का ही यत्न किया है ।

हमने कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद चीन के साथ समझोते करने हेतु लम्बो प्रस्तावों बिना किसी शर्त के पूर्णतया स्वीकार किया है । परन्तु चीन ने इन प्रस्तावों का स्वीकार नहीं किया और वह समझौता केवल अपनी शर्तों पर ही चाहता है । पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ एसी ही है । इसलिये इन दशों के साथ समझौते की बात करने का अर्थ है आक्रमण तथा धमकी के आगे झुकना । आशा है कि हमारी सरकार ऐसा नही करेगी । चीन और पाकिस्तान का मुकाबला शक्तिशाली सेना तथा देश में एकता के साथ किया जा सकता है । यदि पाकिस्तान ने चीन के साथ मित्रता बढ़ाई तो उसको भी दूसरे एसे देशों की तरह हानि उठानी पड़ेगी ।

चीन का एक मात्र सिद्धान्त यह है कि समस्त एशिया में उसका प्रभुत्व हो, चीनी समाज हो तथा एशिया के देशों भी चीन की तरह की ही सरकार हो । चीन नहीं चाहता कि एशिया के किसी देश में दूसरी प्रकार की सरकार हो । हमें इस तमाम चीज को समझने में कोई गलती नहीं करनी चाहिये । पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी ही है । हमने पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिये नहरों के पानी सम्बन्धी समझौता किया । उसको हर प्रकार की रियायत दी परन्तु उस देश ने हमारे प्रति सदा शत्रता का रवैया अपनाया है । इस लिये उसने चीन के साथ साठगांठ भी कर ली है ।

अफ्रीका तथा एशिया के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना एक कठिन कार्य था विशेषकर चीन के आक्रमण के पश्चात जब उन देशों में हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी । परन्तु अब चीन का महत्व उन देशों में लगभग समाप्त ही हो गया है । इसलिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय को चाहिये कि अफ्रीका तथा एशिया और दक्षिण अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के विषय को उच्चतम प्राथमिकता दे । इस बारे में हमें अपने प्रयत्नों में ढील नहीं आने देनी चाहिये । उन सब देशों में हमारे देश के लिये सदभावना है परन्तु हमने अभीतक विश्व के उस भाग के देशों के साथ अपने सम्पर्क का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं किया है । हमें उन देशों में अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अधिक यत्न करने चाहिये ।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

[श्री अ० कु० सेन]

कुछ क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है और हम दूसरे देशों की सहायता करने योग्य हैं। अफ्रीका, अमरीका विशेष कर दक्षिण अमरीका के बहुत से देश हमारे साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग करने को तयार हैं। इस प्रकार एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने से राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें अच्छ सम्बन्ध बनते हैं। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : All possible attempts were not made at Tashkent to save the life of Late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. On the other hand attempts have been made to conceal the truth. Government's failure in that respect is clear and it should resign. Parliamentary inquiry should be held into this matter.

We should have a balance between our foreign policy and resources. There is a shortage of foodgrains in our country and this situation is going on permanently. It has compelled us to adopt a weak policy. Foreign aid is also dangerous for our country till we become strong enough to utilize that aid for modernisation.

Our Government has not been able to do anything in regard to the Rhodesian problem. It has also not adopted a clear policy toward Vietnam problem. It proves the weakness of our foreign policy.

The opposition parties should also adopt a clear attitude if they wish to pursue a proper foreign policy in democracy. Opposition should formulate a policy for uniting India and Pakistan. The Government cannot do like this because they are responsible for the division of the country. It is surprising that even today we have diplomatic relations with China. We should reconsider our policy in regard to China. So far as the question of our border with China is concerned, it should be kept in mind that natural watersheds such as Kailash, Mansorover and Brahmputra and only then we should have any settlement with them. That will only be an honourable settlement . We talk so much of equality but the fact remains that not even single Harijan or Adivasi has been appointed as ambassador so far. In 1947 when present Chief of Army Staff General Choudhury was Brigadier, he said that Indian Army would help in uniting India in future. I do not know what he will do now when he is an army chief.

Shri Heda (Nizamabad) : We cannot make any assessment in regard to the achievements of our Prime Minister's recent visit to various countries although some of the results received are very encouraging. Although she has made her impact on those countries yet only the future will till be so successful she had been in her purpose.

We are following a certain policy in regard to East Germany, Israel, Taiwan and Korea. When this particular policy was framed the circumstances was different. Now these circumstances have been changed and under these changed circumstances we should reconsider our policy in regard to those countries to suit our national interests.

We have to examine the conditions and changed circumstances under which we are called upon to function or act today. We have to gear-up our diplomatic channels and strengthen economic and cultural relations with other countries.

China is, no doubt, our biggest enemy. But we are not in a position to enter into any treaty with other countries against the menace from China. To do so is not only difficult but undesirable also. However, it is absolutely necessary for us to

revise our foreign policy at times in the light of the political exigencies. We should try, as far as possible, to strengthen our economic and cultural relations with important countries in particular.

I got an apportunity to visit African countries as a member of the Indian delegation recently sent to Africa and I realise that Africa is going to occupy the most important position in the near future. Hence there is need to create a separate cadre for foreign services particularly for Indian Embassies in Africa. French language occupies a dominant place in Africa and it is, therefore, necessary for those posted in Indian Embassies there to have a working knowledge of French language also in order to perform their duties properly and efficiently.

We can display these countries a fine picture Indian culture, customs, traditions and ideology through the help and cooperation of those Indians who have settled there. Indian films are very popular in Africa and we can also depict a vivid and ideal image of our country through these films. Alongwith feature films, we should display documentary films also.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : सभापति महोदय, वैदेशिक कार्य मंत्रालय अपने कार्य में सुस्त और रुढ़िवादी रहा है, मैंने संसद् सदस्यों के शिष्ट मंडल के एक सदस्य के रुप में हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों की यात्रा की जिसके आधार इस मंत्रालय के बारे में मैंने ऐसा ही अनुभव किया है।

हमें अफ्रीका में पाकिस्तान द्वारा किये गये भारत विरोधी-प्रचार का, जो शरारती तथा मिथ्यापूर्ण है, सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के इस प्रचार ने अफ्रीकी देशों, विशेषत: उन देशों के नेताओं पर गहरा प्रभाव डाला है। यह देखकर हमें बहुत खेद हुआ है कि वहां पर पाकिस्तानी प्रचार का खण्डन करने त । हमारी नीतियों के बारे में कुछ गलतफहमियां दूर करने के लिये हमारे प्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये बैठ जायेंगे।

लमडिंग तथा डीफ् रेल्वे स्टेशनों पर हाल के विस्फोटों के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SITUATION ARISING OUT OF RECENT EXPLOSIONS AT LUMDING AND DIPHU RAILWAY STATIONS

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि नियम 185 के अन्तर्गत रेलवे मंत्री ने लोक सभा को चालू सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की है :

'कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग और डीफू रेलवे स्टेशनों पर क्रमश: 20 और 23 अप्रैल, 1966 को हुये विस्फोटों से जिनके फलस्वरुप बहुत से व्यक्ति मरे और घायल हुए एवं सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची, उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।"

इस सम्बन्ध में कार्यवाही चार बजे आरम्भ होगी।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : श्री मनोहरन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री मनोहरन : पाकिस्तान ने वहां यह प्रचार किया हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण किया है और पाकिस्तान जसे छोटे देश के लिये जिसकी आबादी 10 करोड़ है 46 करोड़ की आबादी वाले भारत के विरुद्ध आक्रमण करना असंभव है। उन्होंने यह भी प्रचार किया है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। अफ्रीकी देशों के नेताओं को यह बिल्कूल नहीं बताया गया है कि भारत मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

जहां हमने उन्हें यह बताया कि पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिये हमारा 205 वर्ग मील क्षेत्र चीन को दे दिया है, तो उन्होंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। खेद की बात तो यह है कि ट्यूनिशिया में नियुक्त हमारे राजदूत को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

मोरक्को के नेताओं के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हमसे कहा कि भारत तथा पाकिस्तान को अपने मतभेद दूर करके पारस्परिक सम्बन्ध सुधारने चाहिये। उन्होंने काश्मीर में जनमत संग्रह की भी बात की और हमने उन्हें बताया कि जनमत के समूचे संदर्भ में परिवर्तन हो गया है। हमने इस सम्बन्ध में उन्हें बताया कि पाकिस्तान द्वारा हमारे राज्यक्षेत्र का 2050 वर्ग मील भूभाग चीन को दिये जाने के पश्चात् काश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान ने एक तीसरा तत्व ला खड़ा किया है और इस से स्थिति में पूर्णत: परिवर्तन हो गया है। मोरक्को के विदेश मंत्री ने एक बात पूछी कि सभी जगह इस बात की चर्चा है कि काश्मीर के लोग आत्म-निर्णय चाहते हैं और जनमत संग्रह करना पूर्णत: लोकतंत्रीय पद्धति है। तो फिर भारत इस मूलभूत प्रस्तावना को क्यों नहीं मानता। तब उन्होंने मोरीतानिया के बारे में उदाहरण दिया कि मोरीतानिया के मोरक्को का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने उसके लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन किया था। ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट ने तो यह भी कहा कि "आत्म-निर्णय करना एक मान्य सिद्धान्त है और भारत को उसका अनुसरण करना चाहिये"। दुर्भाग्य से हमारे राजदूत ने हमारा पक्ष उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि उनको इस बारे में समुचित जानकारी नहीं है और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने उन्हे इस बारे में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। मोरीतानीया को भारत सरकार ने तुरन्त मान्यता नहीं दी। किन्तु जब लगभग एक वर्ष बाद उसे मान्यता दी तो उसके बारे मे मोरक्को स्थित हमारे राजदूत को कोई भी सूचना नहीं दी गई। उन्हें यह जानकारी मोरक्को सरकार से प्राप्त करनी पड़ी। विश्व में कहीं भी ऐसी बात नहीं होती। वैदेशिक कार्य मंत्री को देखना चाहिये कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावास उचित रूप से कार्य करें और हमारे राजदूतों को हर एक चीज के बारे में समय-समय पर समुचित जानकारी दी जाये ताकि वे हमारे दृष्टिकोण तथा स्थिति को अन्य देशों के नेताओं के समक्ष स्पष्ट रुप से प्रस्तुत कर सकें।

जहां तक इन्डोनेशिया तथा उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, सरकार को बताना चाहिये कि वहां पर नये शासन के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है और उसे इस बात के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये कि वहा पर भारतीयों की सम्पत्ति उन्हें पूर्णतया वापस लौटाई जाये।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : सभापति महोदय, उत्तर में जापान के साथ तथा दक्षिण में भारत के साथ एशिया की प्रतिरक्षा का समझौता करने से अथवा भारत और अमरीका के बीच राजनैतिक समझौते से यदि पाकिस्तान अमरीका मित्र हो तो, भारत तथा पाकिस्तान के बीच फेडरल तथा व्यावसायिक आधार पर राजनैतिक समझौते से, अथवा यदि इस प्रकार के समझौते से शक्ति संतुलन रूस के पक्ष में हो तो भारत और चीन के बीच राजनैतिक समझौते से चीन-रूस समझौता दो बारा हो सकता है और यूरोप पर रुसी प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

यदि पाकिस्तान रुस का मित्र हो, तो भारत और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक समझौते से अथवा भारत और चीन के बीच राजनैतिक समझौते से—यदि उससे शक्ति का सन्तुलन रुस के पक्ष में हो—अथवा वियतनाम के मामले पर चीन और अमरीका में राजनैतिक समझौता हो जाने से चीन तथा अमरीका के बीच सन्धी हो सकती है। इससे ब्रिटेन से लेकर उराल की पहाड़ियों तक युरोप में अमरीकी प्रभुत्व स्थापित हो जायगा।

भारत तथा चीन के बीच अथवा काश्मीर के मामले पर एक ओर भारत और दूसरी ओर पाकिस्तान तथा चीन के बीच अथवा वियतनाम के प्रश्न पर चीन और अमरीका के बीच तथा राज्यक्षेत्र सम्बन्धी विवादों के प्रश्न पर रुस तथा चीन के बीच युद्ध छिड़ जाये, तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, तुर्की, ईरान, अफगनिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, सिकियांग, मंगोलिया, मंचूरिया तथा उत्तरी चीन पर रुसी प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा और दक्षिण चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा तट के परे के एशिया पर अमरीकी प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा।

आम तौर पर अफ्रीका तथा एशिया और विशेषतः भारत तथा चीन दो भागों में विभक्त हो जायेंगे। रुसी प्रभाव तथा अमरीकी प्रभाव में अथवा रुस और अमरीका मिलकर यदि अफ्रीका तथा एशिया में ताप-आणविक हथियारों के फलाव को रोकें अथवा यदि भारत और पाकिस्तान के बीच अथवा भारत और चीन के बीच राजनैतिक समझौता हो जायें—यदि पाकिस्तान चीन का मित्र बन जाये अथवा चीन, रुस अथवा अमरीका में से किसी का मित्र न बने, तो ऐसी स्थिति में अफ्रीका तथा एशिया में रुसी-अमरीकी प्रभाव समाप्त हो जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, the more we are trying to make our position on Kashmir clear abroad, the more intricate and complicated its internal problems are getting.

There has been a definite shift in the stand of the Communist Party on the question of Kashmir. Formerly, it used to say that every inch of Kashmir belonged to India but today it is of the view that the cease-fire line might be regarded as the international border.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सभा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर हुये विस्फोटों के बारे में प्रस्ताव पर कार्यवाही आरम्भ करेगी।

लमडिंग तथा डीफू रेलवे स्टेशनों पर हाल के विस्फोटों के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : SITUATION ARISING OUT OF RECENT EXPLOSIONS AT LUMDING AND DIPHU RAILWAY STATIONS

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग और डीफू रेलवे स्टेशनों पर क्रमशः 20 और 23 अप्रैल, 1966 को हुये विस्फोटों से, जिनके फलस्वरुप बहुत से व्यक्ति मरे तथा घायल हुये एवं सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची, उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।"

[श्री स० का० पाटिल]

हम सभा तथा जनता की चिन्ता को भलीभांति समझते हैं जब हर रोज इस प्रकार की घटनाएं घटें तथा उनके परिणामस्वरुप कई लोगों की मृत्यु हो। इन दो घटनाओं में एक सौ से अधिक व्यक्ति मरे और 200-300 के लगभग व्यक्ति घायल हुये हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुनः ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

ये घटनाएं रेलवे के नियमित काम नहीं हैं क्योंकि पिछले 113 वर्षों में जब से देश में रेलगाड़ियां चलती हैं, हमें इस प्रकार की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा है। इनका रेलवे के कामों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिससे इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। वह उन लोगों का काम है जो भय तथा अन्य कई चीजें फैलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी योजना है कि समय-समय पर होती रहें।

सभा को अच्छी तरह विदित है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे क्षेत्र हाल ही बनाया गया था। इस रेलवे पटरी की कुल लम्बाई 457.1 कीलोमीटर है किन्तु इसका कुछ भाग दोहरी लाइन है अतः उसकी पूरी लम्बाई 3207 किलोमीटर है। वहां पर निरन्तर 10 रेलगाड़ियां चलती है और औसतन तीन से चार हजार व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करते हैं। वहां पर 444 स्टेशन हैं परन्तु लमडिंग-सिमुलगुड़ी क्षेत्र में केवल 34 स्टेशन हैं। ——यही क्षेत्र सबसे अधिक खतरनाक क्षेत्र है——नागालैंड सीमा पर 231 किलोमीटर का क्षेत्र——और लमडिंग डमचेरा अंचल (सेक्शन) में 155 किलोमीटर लाइन है और वहां 14 स्टेशन हैं। इस प्रकार वहां 48 स्टेशन सुरक्षित नहीं हैं। और उनकी हमें सुरक्षा करनी है। पिछले नौ वर्षों से इस क्षेत्र की सुरक्षा का भार सेना को सौंपा हुआ है क्योंकि रेलवे के लिये यह कार्य कठिन था।

इस क्षेत्र में घने जंगल, दलदल तथा पहाड़ हैं। इस बात की मांग की गई थी कि जंगल साफ किया जाये हम सारा जंगल साफ़ नही कर सकते। केवल नागालैंड की ओर का ही एक भाग साफ किया जा सकता है। ऐसा निर्णय किया गया है कि नागालैंड सीमा पर 500 गज तक क्षेत्र साफ किया जाये किन्तु वहां इतनी अधिक वर्षा होती है कि यदि जंगल साफ गिया भी जाये तो वह छः महिने के भीतर फिर उग जाता है। इस लिये वहां लगातार सफाई करना जरुरी है और ऐसा किया भी जा रहा है।

अब मैं उन उपायों के बारे में बताऊंगा जो हमने अब तक किये हैं और जिन्हें हम आगे करना चाहते हैं। उन भागों में सभी पैसेंजर एक्सप्रेस, तथा मेलगाड़ियों के आगे सर्चलाइट स्पेशल गाड़ी होती है और उनकी सुरक्षा के लिये सशस्त्र सैनिकों की व्यवस्था की जाती है। पटरी को सुरक्षित रखने तथा छुपकर गोलियां आदि चलाने को रोकने के लिये ऐसी व्यवस्था की गई है। बमों से इसका कोई संबंध नहीं है और जहां कहीं बम रखा जाता है वहां यह व्यवस्था निष्फल हो जाती है, जैसा कि 20 तथा 22 तारीख की घटनाओं में हुआ है।

इन दोनों सेक्शनों में सामरिक महत्व के सभी-स्थानों पर सशस्त्र पुलिस दल के दस्ते तैनात किये गये है और वे रेलवे स्टेशनों, पटरी तथा पुलों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। सेना तथा सशस्त्र पुलिस दस्तें समीपवर्ती जंगल में भी गश्त लगाते हैं और उनमें से कुछ दस्तों को आसाम के साथ लगने वाली नागालैंड की सीमा के साथ-साथ सामरिक महत्व के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के इंजिनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को निगरानी करने तथा तोड़-फोड़ के मामलों की सूचना निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को देने के लिये विभिन्न पुलों तथा सुरंगों पर तैनात किया गया है ताकि रेलगाड़ी-दुर्घटनाएं रोकी जा सके। इस प्रकार 37 सुरंगों तथा 34 पुलों की सुरक्षा की जा रही है।

इन सेक्शनों में सभी माल गाड़ियों की सुरक्षा के लिये उनके साथ सशस्त्र पुलिस भेजने की व्यवस्था की गई है।

वहां रेलवे घने जंगलों तथा दलदल से गुजरती है विशेष रुप से लुमडिंग-मनीपुर रोड तथा मनीपुर रोड तथा सालुपहाड़ के बीच उस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। जगल लगातार साफ किये जा रहे हैं परन्तु जंगल साफ किये जाने के बाद शीघ्र पुनः उग जाते हैं।

16 फरवरी, 20 अप्रैल तथा 23 अप्रैल की घटनायें एक जैसी है। इस से नई समस्या पैदा हो गई हैं। हम सामान, बक्से आदि देखने का प्रयास करते है यद्यपि इस प्रकार पता लगाना कुछ असम्भव है क्योंकि यात्रियों तथा स्टेशनों की संख्या इतनी अधिक है कि केवल झांक कर देखना ही सम्भव है। यह प्रक्रिया हमने इसलिए आरम्भ की है क्योंकि हम इस सम्बन्ध में कुछ पता करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में यात्रियों के खतरे को कम करने के लिए एक उपाय यह किया गया है कि लमडिंग तथा मरियानी के बीच रात के १० बजे से प्रातः ४ बजे तक यात्री गाड़ियां चलाना बन्द कर दिया गया है, इसी प्रकार लमडिंग डमचेरा सेक्शन में रात के सात बजे से प्रातः चार बजे तक गाड़ियां चलानी बन्द कर दी गई है।

नागालैंड की ओर 1500 फुट तक तथा आसाम की 300 फुट तक जंगल साफ करने तथा रेलवे के साथ साथ सड़क बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है परन्तु यह सभी केवल पूर्वोपाय ही हैं। मेरे विचार में ऐसी बातों के विरुद्ध एकमात्र व्यावहारिक कार्यवाही बदले की कार्यवाही की अनुमति देना होगी। हम इस प्रकार शरारत करने वालों से नम्रता से नहीं निपटेंगे। हमें आशा थी कि जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे है तब वे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे।

इस बात का लगातार डर रहता है कि ऐसी घटनायें पुनः हो सकती हैं। वे बम देश में अथवा पाकिस्तान में नहीं बने हैं। वे विदेशों से मंगाये गये हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे बम रख सकता है। शान्ति की वार्ता करने वालों में से किसी ने भी इन गतिविधियों की निन्दा में वक्तव्य नहीं दिया है। यह ऐसी बात है जिससे रक्त खोल उठता है। कोई भी ऐसी गतिविधियों को नहीं समझ सकता जिससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो जाये। वे यात्री छिपे हुये नागाओं से नहीं लड़ रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जहां तक रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा दल का सम्बन्ध है, वे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए जो भी सम्भव होगा, करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग और डीफू रेलवे स्टेशनों पर क्रमशः 20 और 23 अप्रैल को हुये विस्फोटों से, जिनके फलस्वरुप बहुत से व्यक्ति मरे और घायल हुए एवं सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची। उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।"

Shri Ram Sewak Yadav : I move my substitute motion.

श्री मधु लिमये : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रंगा (त्रिचूर) : श्रीमान्, इस दुर्घटना पर शोर तथा दुख उत्पन्न करते समय मैंसभा के सभी वर्गों की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। यह दुर्घटना न केवल रेलवे के लिए अपितु हमारे लोकतन्त्र के लिए भयंकर दुर्घटना है कि दो अवसरों पर एक सो निर्दोष व्यक्ति उन लोगों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से पीडित हुये जो अवश्य ही बिलकूल पागल हो गये होंगे। रेलवे मंत्री द्वारा सभा को आश्वासन देना उचित था। इस मामले से प्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित मंत्रियों के लिए यह अधिक अच्छा था कि वें सभा को विश्वास में लेते तथा हमें यह बताते कि वे क्या करना चाहते है और वे बुरी तरह से असफल क्यों रहे हैं? ऐसी घटना पहली या दूसरी बार नहीं हुई है परन्तु मेरे विचार में तोड़-फोड़ की यह कार्यवाही नौंवी बार हुई है। हम सेना को दोष नहीं दे सकते क्योंकि सेना ने पहले ही वहां 6 मोर्चे सम्भाल लिए है तथा यात्रियों की यथासम्भव सुरक्षा करने के लिए वह जिम्मेवार है। फिर भी, अधिक कार्य नहीं किया गया है। उसके लिए सरकार के अतिरिक्त और किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

[श्री रंगा]

अभी तक नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति की बातचीत जारी रखने में सरकार तथा विरोधी दल सहमत थे परन्तु विद्रोही नागाओं ने भारत से, अपने आप से, आसाम से और समूचे देश में रहने वाले आदिम जातियों के लोगों से ठीक व्यवहार नहीं किया है। प्रधान मंत्री और सरकार के साथ बातचीत के दौरान उन में से कुछ ने इन भयंकर घटनाओं के लिए अपने आप को उत्तरदायी माना है। उन्हें इन भयंकर घटनाओं के लिए नहीं बल्कि अपने अनुयाइयों के अनुशासन में न रहने के लिए अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिये।

हमें रेलवे कर्मचारियों तथा यात्रियों की प्रशंसा करनी चाहिये कि वे इन सभी घटनाओं के बावजूद रेलों से यात्रा करते हैं। रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह नहीं बताया गया है कि क्या उन्हें कोई विशेषाधिकार और प्रशिक्षण प्राप्त है तथा आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण दिये जा रहे हैं इसके साथ ही उनके वतन तथा भत्ते आदि में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

मैं नागा समस्या को आसाम सरकार पर छोडने के पक्ष में नहीं हूं। वह केवल ब्रम्हपुत्र घाटी के लिए ही उत्तरदायी होनी चाहिये। बर्मा, चीन तथा पाकिस्तान के साथ वे स्वायत्त सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी होनी चाहिये तथा उसे समूचे क्षेत्र की पूरी सुनिश्चित करनी चाहिये। तब ही हम अपने रेलवे यात्रियों और उस क्षेत्र में अन्य लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे।

हम यह समस्या केवल सुरक्षा समस्या के रूप में हल नहीं कर सकते। हमें यह समस्या विधि तथा व्यवस्था की समस्या के रुप में और आदिमजाति क्षेत्र के लोगों के सामाजिक विकास के रुप में हल करनी चाहिये। हमें उनके साथ सम्भावित, आदरणीय और प्रिय नागरिकों जैसा व्यवहार करना चाहिये। क्योंकि बहुत समय से उनकी उपेक्षा की जा रही है। उनकी सहायता के लिए किये जाने वाले सामाजिक कल्याण सम्बन्धी व्यय में वद्धि की जानी चाहिये ताकि वे भारतीय नागरिकता पर गर्व करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) :अध्यक्ष महोदय, सारे देश में और इस सभा में भी इस बात का दु:ख महसूस किया जा रहा है कि हमारे देश में आजकल भी ऐसी घटनायें हो सकती हैं। देश में जो कोई भी घटनायें हों उनकी जिम्मेवारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। सरकार को भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिये भी कोई नीति अपनानी चाहिये।

रेलवे मंत्री ने ठीक ही कहा था कि ये घटनायें रेलवे की अफसलता के कारण नहीं हूई हैं। यदि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचा जाये तो यह सारी सरकार की ही असफलता है। जो कुछ घटनायें हुई हैं उनसे पता चलता है कि हमारे राजनीति निकाय में ऐसा रोग लग गया है जिसका उपचार किया जाना चाहिये। परन्तु हमें इसका उपचार सोच समझ करऔर सहानुभतिपूर्वक करना होगा।

ये जो घटनायें हुई हैं वे उलझनवाले क्षेत्र में हुई हैं। यह क्षेत्र ऐसे क्षेत्र के पास हैं जहां नागा लोग इतने समय से विद्रोह करते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में ही मिजो लोगों ने विद्रोह किया था। कुछ ही दिन पूर्व डाक्टर स्वेल ने प्रैस सम्मेलन में बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर भागों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग किस तरह से असन्तुष्ट हैं कि काम इस तरह से नहीं किया जा रहा है जिस तरह से वह होना चाहिये। अत: सरकार को उनके असन्तोष की ओर ध्यान देना चाहिये और ऐसी नीति भी बनानी चाहिये जिस से स्थिति का जरूरत के अनुसार मुकाबला किया जा सके।

हमारी ऐसी समस्यायें दिन-प्रति दिन बढ़ रही हैं। कुछ विदेशी शक्तियां हमारी इन समस्याओं से लाभ उठाना चाहती हैं। जब लगभग 15 मास पहले हम में से कुछ संसद सदस्य नागालैण्ड गये हुए थे तो हमें बताया गया था कि हमारे पड़ोसी देशों ने अमरीका के बने हुये हथियार नागा विद्रोहियों को सप्लाई किय जाते हैं। आज सुबह हमें बताया गया था कि इस क्षेत्र में खल लोगों ने फ्रांस के बने हुए रॉकेटों का प्रयोग किया है। हमें यह भी पता है कि पादरी माइकेल स्कॉट जैसे वफादार लोगों के जरिये अंग्रेज लोग नागालैण्ड को पृथक् करने में रुचि ले रहे हैं।

चीन भी हमारी सीमाओं पर रहने वाले आदिम जाति लोगों को हम से जुदा करना चाहता है। इसलिये हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो हमारे उपेक्षित आदिम जाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में ऐसी भावना पैदा कर दे जिससे वे भी अपने आपको भारत के शेष लोगों के समान समझें।

मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में नागाओं पर सन्देह करना स्वाभाविक ही है परन्तु हमें पहले से ही सन्देह नहीं करना चाहिये। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इन घटनाओं में छिपे नागाओं का हाथ है तो निश्चय ही सरकार उनसे कानूनी तौर पर निपट सकती है परन्तु किसी प्रमाण के आधार पर ही हमें अपने मामलों को आगे बढ़ाना चाहिये।

सरकार को इस संबंध में ऐसा रवैया अपनाना चाहिये जो मानवता तथा शिष्टता से संगत हो। उसे बल द्वारा शान्त रहने की नीति नहीं अपनानी चाहिये। उसे मित्रता, आर्थिक विकास तथा अधिकतम स्वायत्तता की नीति अपनानी चाहिये। सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लोगों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिये। उसे पाटस्कर समिति के प्रतिवेदन के बारे में कुछ करना चाहिये। शायद उसकी सिफारिशें व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने से कुछ परिणाम निकल सकें। सरकार को नागालैण्ड अथवा मिज़ो क्षेत्र आदि को अधिकतम स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। उन लोगों को प्रसन्नता से भारतीय समुदाय में रखने के लिये यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन भी करना चाहिये। इस मामले में रेलवे पर कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। इसकी ज़िम्मेवारी सरकार पर है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The anarchy in Nagaland is due to the lenient policy of the Government. I am sorry to say that neither Rev. Michael Scott nor the Chief Minister of Assam or Nagaland have expressed grief over such happenings. It is high time that the Government gets rid of such peace missionaries. The Government should bring about a radical change in her policies with regard to Nagas. By such happenings Rev. Scott wants to show that he is indispensable and he will continue to remain here as an apostle of peace. It is time that we ask foreign missionaries of doubtful integrity to leave India. If this problem is not solved with a firm hand, disorder will spread to other areas.

The Nagas got arms from foreign countries and they were trained in Pakistan. The Nagas should accept their responsibility as Indian citizens. If they do not want to be the citizens of India, the Government should suppress them with a firm hand. The people of India will not allow the policy of weakness to be continued any longer.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : The Government have moved this motion after the adjournment motion moved by the members of the opposition were rejected. It shows that the Government want to solve this problem with the help of the Members of this House and they do no want to make it a party question.

It is to be noted that such incidents take place when the talks with rebel leaders or members of the Peace Mission are being held. It shows that they do not believe in peace and they want to put pressure on the Government by such acts of sabotage. We should pay serious attention to such matters and make arrangements for the protection of trains and railway property. We may also take help from military in this area. If search of the passengers is not possible, some other method may be devised.

For the time being some such method should be adopted so that any person with explosives may not board a train or enter the station area.

[Shri A. P. Sharma]

Strong action should be taken against persons responsible for these explosions. No mercy should be shown to such anti-national elements. I do not at all agree with Shri Hiren Mukerjee that Government should show some sympathy towards the persons involved in this explosion. Nobody is benefited from such explosions. Prof. Mukerjee has said that Congress Governments policies are very weak. But I want to make it quite clear that the Congress Government considers it its duty to deal with such subservise elements with a firm hand.

Government should give thought to the question of prolonged talks with rebel Naga leaders and the continuance of such incidents. Government should take some positive steps in this direction so that Government property may be protected and the people of that area may live in freedom, peace and without any fear there as people in otner areas of India live.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित) (आंग्ल-भारतीय) : मैं इन आतंक उत्पन्न करने वाली तथा हिंसात्मक घटनाओं की निन्दा करता हूं जबकि मेरी धारणा के अनुसार इनके पीछे नागाओं का हाथ है जो अधिकतर ईसाई धर्म के अनयायी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निर्दोष व्यक्तियों जिनमें महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं की जानबूझकर हत्या की गयी है। अत: सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नागा समस्या स्वयं सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है क्योंकि यदि नागालैण्ड पहले ही बना दिया जाता तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। मेरी राय में ऐसी बातों में जाना ठीक नहीं है। नागा लोग बहुत ही सीधे साधे तथा भोले होते हैं और उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है।

अब नागालैण्ड बन गया है और नागाओं को पूरी स्वायत्तता प्राप्त है और वे अपने भाग्य के बारे में स्वयं फसला कर सकते हैं और जब तक नागालैण्ड अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता तब तक वह अपनी आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिये इस समूचे देश के संसाधनों पर निर्भर कर सकता है। चूंकि वे भी हमारी तरह भारतीय ही हैं इसलिये मैंने नागा समस्या का उल्लेख नहीं किया। मैं श्री मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में सरकार को बहुत सबर से काम लेना चाहिये। और मेरी राय में सरकार ने इस मामले में मानवता का सबसे अधिक परिचय दिया है और वह आगे से ऐसा ही करती रहेगी। जब सरकार भूमिगत नागाओं से निपट रही थी तो हमारे दिल में कुछ आशंकायें थी। मैं महसूस करता था कि केन्द्रीय सरकार ने शीलू आओं की सरकार से हुई बातचीत को अधिक महत्व नहीं दिया जिससे शीलू आओ की सरकार और वफादार नागाओं की शक्ति क्षीण हुई है।

दूसरी आशंका यह थी कि शुरू में ही एक विदेशी को इस समस्या से सम्बद्ध करने की गलती नहीं की जानी चाहिये थी। उसको बुरा भला कहने से कोई लाभ नहीं है। हमें उसकी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। वह नागाओं का भावी इतिहासकार बननः चाहता है और ऐसा बताया जाता है कि वह तथाकथित इतिहास की खोजबीन कर रहा है जिससे कि नागा लोग अपनी हठ पर कायम रह सकें और उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे सदैव अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र रहे थे। जैसा मैंने कहा हमें उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये और इस भूल को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिये।

एक और आशंका यह थी कि इस शांति वार्ता के दौरान छिपे हुए नागा अपनी संख्या बढ़ाने तथा धन जुटाने के काम में लगे रहे हैं। इसके अलावा मनीपुर में युद्धविराम लागू करके सरकार ने बड़ी भारी भूल की है। मनीपुर में कोई नागा समस्या नहीं थी। वहां युद्धविराम का विस्तार करके सरकार ने छिपे नागाओं को वफादार नागाओं से धन ऐंठने तथा उन्हें आतंकित करने के लिये खुला निमंत्रण दिया है। यह स्पष्ट है कि अब नागाओं की सामरिक नीति मनीपुर के रास्ते मिजो लोगों से सम्बन्ध स्थापित करना और आसानी से पाकिस्तान पहुंच सकना है।

मिजो लोग असम लोगों को पसन्द नहीं करते हैं। मुझे विश्वास है कि पाटस्कर आयोग ने सिफारिश की थी कि मिजो क्षेत्र केन्द्र शासित क्षेत्र होना चाहिये। जहां तक सैनिक सहायता का सम्बन्ध आसाम सरकार कुछ नहीं कर सकती है और वह आर्थिक सहायता देने की स्थिति में भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि अल्प संख्यक लोगों को राज्य सरकारों की बजाय केन्द्रीय सरकार में अधिक विश्वास है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि नागालैण्ड के बनने से नागा लोग अपना भाग्य का स्वयं फैसला कर सकते हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। नागाओं के इस आतंक तथा हिंसा का सामना करने के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले सरकार को उन्हें बता देना चाहिये कि यदि वे भारत संघ के अन्दर रहते हुए सरकार से बातचीत करने के लिये तैयार हैं तो सरकार उनकी अधिकांश बातें मानने को तैयार है। यदि वे भारत संघ के अन्तर्गत रह कर बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है तो सरकार को कोई दृढ़ निर्णय करना होगा। मुझे बहुत भारी दिल से यह कहना पड़ रहा है। अब सेना चुप बैठने के लिये तैयार नहीं है। यदि नागा लोग बहकावे में आकर फिर से ऐसी हरकतें करते हैं तो उनसे निबटने के लिये सरकार को सेना को पूरी स्वतंत्रता देनी होगी। इससे लोगों की जानें जायेंगी परन्तु इस समस्या के हल के लिये इस के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह जाता।

Shri R. S. Pandey (Guna) : Hundred people have lost their lives and hundreds other persons were injured as a result of these two explosions within a span of only 4 days. It appears that there is an organised conspiracy and rebellion behind this whole affair. Nagas are a part of us and all of them are not rebels. We want that they should live like respectable citizens as others live. We value their culture and are always prepared to disucss with them their economic, social and political problems in pursuance of the provisions laid down in the constitution. If in spite of such sentiments, the Naga rebels indulge in acts of terrorism and violence, this matter assumes serious proportions and constitutes a threat to our democracy.

These incidents will have serious repurcussions on the people in this country and they will form an opinion that the Government has grown so weak that it is unable to handle only 2 or 3 thousand Naga rebels. In this context, we would suggest that the Ministry of Home Affairs should take over the task of maintaining law and order in Nagaland from the External Affairs Ministry into its own hands without any further delay.

The recent happenings are an indication of the fact that Mr. Michael Scott is responsible to a very great extent for all this trouble in that area. There is no justification for extending his stay here for another month. He should be asked to leave India immediately.

The Peace Mission has not achieved any success in its mission so far. It should be dissolved. Before the Prime Minister initiates any talks with Naga rebels in future, they should first admit that they had a hand in these incidents and that they are sorry for this act of theirs. If they are not preared to do so, no talks should be held with them and Government should take stringent action against these rebels so that they may not indulge in such activities in future.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Government's uncertain policy in regard to the Naga problem is responsible for these happenings. Unless this policy is set right, this problem will remain as it is. Government has been following a policy of appeasement and of repression so far as Naga people are concerned. Government has failed to adopt a practical and proper policy in this repect so far We have been told that there has been a definite progress in establishing peace in that area but these happenings are an indication of the fact that there is no peace in that area.

[Shri Ram Sewak Yadav]

Even the statements made by the hon. Ministers contradict each other. The Railway Minister stated that these explosives were not manufactured in India, whereas the Minister of Home Affairs stated that such explosives can be manufactured in India as well. One Minister terms the situation as very serious. But another hon. Minister is not prepared to accept the fact that the situation is so much serious. This is the way in which the Government is functioning.

Such happenings have been constantly on the increase.

Government has failed to protect the lives and properties of the citizens. It should revise its present policy of appeasement and repression in regard to the Naga people. Under the Defence of India Act Government has a direct responsibility so far as Nagaland is concerned as it is a border area, and Government has failed to discharge its duty towards this state.

श्री बसुमतारी (गोआलपाड़ा) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन घटनाओं में विद्रोही नागाओं का हाथ है और कुछने कहा है कि इनके पीछे मिजो लोगों का हाथ है। परन्तु रेलवे मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन घटनाओं में विदेशियों का हाथ है। आसाम राज्य के टुकड़े करके इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मिजो पहाड़ी क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने से भी यह समस्या हल नहीं हो सकती। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि एक पृथक पहाड़ी राज्य बनाया जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नागा लोगों को आसाम सरकार में विश्वास नहीं है। इस तरह की बात कहना बहुत ही खतरनाक है। हमें इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना है। जब तक आसाम सरकार के हाथ मजबूत नहीं किये जायेंगे तब तक भारत सरकार कुछ नही कर सकेगी। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। पहाड़ी आदिम जातियों के लोगों के बारे में कोई निर्णय लेते समय सरकार को केवल वहां के मंत्रियों से ही नहीं अपितु उस क्षेत्र के लोगों से भी सलाह लेनी चाहिये।

इस सारी समस्या के पीछे भारतीय असैनिक सेवा के एक अधिकारी का हाथ है जो यह नहीं चाहता था कि भारत को आजादी मिले। उसका नाम श्री केलवर हो था और वह कामरूप जिले का डिप्टी कमिशनर था। कुछ समय पश्चात उसकी नागा पहाड़ी क्षेत्र में बदली कर दी गई थी। उसने कुछ विद्रोही नागाओं की सहायता से भारत सरकार को गुमराह किया। श्री फिजो तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नेहरू से मिलना चाहते थे क्योंकि श्री फिजो उस समय अपने को गांधी जी का चेला मानते थे। परन्तु उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर वहां गये थे और उनसे मिलने के लिये वहां पर बहुत से लोग एकत्र हो गये थे। परन्तु उस अधिकारी ने उन्हें श्री ढेबर से नहीं मिलने दिया और अपने कुछ आदमियों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष को जो वह कहलवाना चाहता था कहलवा दिया। इन गलतियों के लिये केन्द्र जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं।

एक बार यहां पर राज्य सरकार के विरुद्ध प्रचार किया गया था और वही प्रचार इन सब घटनाओं के लिये जिम्मेदार है। पहाड़ी आदिम जातियों के लोगों ने पहले कभी कोई बड़ा आन्दोलन नहीं किया था परन्तु जब से नागालैण्ड बनाया गया है तबसे ये लोग भी पृथक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे है। सरकार नहीं समझती कि गलती कहां हुई है।

यह बड़ी विचित्र बात है कि समाचार पत्र भी विद्रोही नागाओ के वक्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं और वफादार नागाओं के वक्तव्य को बहुत ही कम।

प्रधान मंत्री को स्थिति की गम्भीरता को समझना चाहिये और उन्हें केवल नागा विद्रोहियों से ही बातचीत नहीं करनी चाहिये अपितु उन नागाओं के विचार भी जानने चाहिये जो शांति तथा देश की एकता में विश्वास रखते हैं तभी यह समस्या हल हो सकती है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : नागा विद्रोहियों द्वारा लमडिंग तथा दीफू स्टेशनों पर किये गये विस्फोट बहुत ही दुखद हैं। परन्तु यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा शीघ्र सहायता नहीं पहुंचाई जाती है। इसलिये यह सम्भव है कि कुछ लोग, जिन्हें चोटें आई थीं, रात्रि के दौरान जीवित हों परन्तु समय पर चिकित्सा न किये जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। क्यों रात के समय शवों की खोज ही नहीं की गई थी। वास्तव में ऐसी घटना होने पर रेल अधिकारियों द्वारा हवा में भोंपू बजाया जाना चाहिये था। परन्तु लमडिंग स्टेशन पर ऐसा नहीं किया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी अथवा सहायक चिकित्सा अधिकारी ने घायलों की देखभाल नहीं की। उनको बरामदे में भर दिया गया और दो छोटे डाक्टरों ने 150 से अधिक घायलों को देखा। ये बहुत ही दुःखद बातें हैं और इसलिये मैंने इनका जिकर किया है।

इन दुःखद घटनाओं को इक्का दुक्का घटनायें नहीं कहा जा सकता। वे ब्रम्हपुत्र घाटी में संचार के साधनों में बाधा डालने की नागा विद्रोहियों की नीति का ही एक भाग है। 7 मार्च को नागा फैडरल सरकार के तथाकथित मंत्रियों से छीने गये दस्तावेजों तथा कागजों से इस समूची नीति का स्पष्ट चित्र मिलता है। इन सब लोगों को आसाम के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप करने पर छोड़ दिया गया था।

इन कागजात तथा दस्तावेजों के पकड़े जाने के बावजूद भी हमारा गुप्तचर विभाग लमडिंग तथा डीफू में हुई दुर्घटनायों में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका है।

कुछ लोगों के दिल में यह सन्देह है कि शायद कोई भी विदेशी शक्ति इनको प्रोत्साहन नहीं दे रही है। मुझे इस बात की पक्की सूचना है कि चीन के नेताओं की पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान मिज़ो तथा विद्रोही नागाओं के नेता उनसे डाका मे मिले थे। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है। परन्तु इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन तथा पाकिस्तान मिजों तथा विद्रोही नागाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि मिज़ो तथा नागा लोग केवल आसाम सरकार के विरुद्ध हैं। परन्तु यह बात नही है। वे न केवल आसाम राज्य के अपितु समुचे भारत के विरुद्ध हैं। वे भारत संघ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। वे इस सिद्धान्त को मानते हैं कि एक राज्य में एक से लोक ही रहने चाहिये। 20 दिसम्बर 1964 को नागालैंड शान्ति मिशन ने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे परन्तु विद्रोही नागाओं ने आजतक न तो इन प्रस्तावो को मंजूरी दी है और न ही इनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ही बताई है। दूसरी ओर वे इस बातचीत से लाभ उठाकर अपने आप को अधिक मजबूत कर रहे है। उन्होंने अपने प्रशासन को मनीपुर की उपरुल सब-डिविजन तक बढ़ा लिया है। अभीतक इस सब-डिविजन में भारतीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई है।

अब समय आ गया है कि सरकार छिपे हुए नागाओं से कहे कि वे लमडिंग, डीफू तथा फदकुटिग मे हुई दुर्घटनाओं की निन्दा करें अथवा उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे गये हैं। यदि छिपे हुए नागा ऐसा नही करते तो हमें उनसे बातचीत तोड़ लेनी चाहिये और अपनी सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश देना चाहिये क्योंकि हम नही चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं पुनः घटें। हमें भारत संघ की एकता बनाये रखनी चाहिये और इसकी अखण्डता का सौदा करने वाले के साथ कठोरता से निपटना चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट करने में अपने आप को सम्मिलित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर घायल व्यक्तियों को शीघ्र अच्छा करे। लगभग दस वर्ष पूर्व छिपे हुए नागाओं ने अपनी भूमिगत गतिविधियों को आरम्भ किया था। उस समय उनके साथ निपटना आसान था क्योंकि उस समय हमारी चीन के साथ मित्रता

[श्री प्र० चं० बरुआ]

थी। परन्तु हमने वह अवसर खो दिया। अब ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि छिपे हुए नागा चीन तथा पाकिस्तान से हथियार ले रहे है। मिजो विद्रोहियों ने भी इसी प्रकार की गतिविधियां आरम्भ कर दी है वे भी पाकिस्तान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहाड़ी लोगों के नेता भी धीरे धीरे अपना सिर उठा रहे हैं। यदि ऐसी गतिविधियों को जारी रहने की अनुमति दी गई तो मैदानी क्षेत्रों के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनकी केन्द्र द्वारा उपेक्षा की जा रही है। अत: वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार को नागालैंड की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के असंतोष से चीन तथा पाकिस्तान लाभ उठा सकते हैं।

नागाओं को यह बता दिया जाना चाहिये कि वे स्वयं ऐसी कार्यवाही करें जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं पुन: न घटें। दूसरे उनको यह भी बता देना चाहिये कि वे भारत संघ से बाहर निकलने के विचार को छोड़ दें। यदि वे इन बातों को नहीं मानते तो उनको राष्ट्रद्रोही तथा शत्रु देशों के एजेन्ट समझा जाना चाहिये तथा उसी प्रकार उनसे व्यवहार किया जाना चाहिये। इसका विकल्प सैनिक कार्यवाही ही है। हमे समय पर कार्यवाही करनी चाहिये। यदि विलम्ब होता है तो नागालैण्ड दूसरा वियतनाम बन जायेगा। आशा है कि सरकार समय पर ही कार्यवाही करेगी और ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी।

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्तशाली जिले) : एक पहाड़ी तथा आदिम जाति सदस्य होने के नाते मैं लोगों की निन्दा करता हूं जो कोई भी इन दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों तथा माननीय रेलवे मंत्री ने यह विचार प्रकट किये हैं कि हो सकता है कि इन दुघटनाओं के पीछ छिपे हुए नागाओं का हाथ हैं परन्तु इस समय जांच हो रही है। इसलिये हमें यह नहीं कहना चाहिये कि यह कार्यवाही छिपे हुए नागाओं की है।

सच यह है कि जिस क्षेत्र में यह दुर्घटनाएं हुई हैं वह आसाम में एक छोटा पाकिस्तान है। 1962 मे जब चीन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां पर पाकिस्तान का झण्डा लहराया गया था। सरकार ने इस बात का खण्डन नहीं किया था। यह सम्भव है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन इन दुर्घटनाओं के पीछे हों। आसाम के मुख्य मंत्री ने कल कहा है कि यह गतिविधियां राष्ट्रद्रोही तत्त्वों की हैं जोकि अब सक्रिया हो गये हैं। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जबतक सरकार को विश्वास न हो जाये कि ये गतिविधियां वास्तव में उन्हीं लोगों की है और वही लोग इनके लिये जिम्मेदार है सरकार को स्पष्ट रूप से कोई वक्तव्य नही देना चाहिये।

यदि नागा इन दुघटनाओं के लिये दोषी पाये जाये तो सरकार को उन्हें अवश्य दण्ड देना चाहिये। परन्तु यदि एसी बात नहीं है तो इस प्रकार के वक्तव्यों से अनावश्यकरूप से दुर्भावना उत्पन्न होगी। यह सच है कि छिपे हुए नागाओं के नेता अथवा वहां की वास्तविक सरकार ने सहानुभूति अथवा खद का एक भी शब्द नहीं कहा है। परन्तु हमें बदला लेने की बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि जब हम नागाओं से बदला लेने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम समस्त नागा जाति से बदला लेना चाहते है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कुछ सर्वोच्च नेता गैर-जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जब मैं मिज़ो हिल्स में गया था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि वहां पर ऐसे समाचार आ रहे है कि भारत सरकार मिज़ो लोगों में रुचि नहीं रखती है बल्कि वह तो केवल भारत की प्रतिरक्षा के लिय ही उस क्षेत्र में रुचि ले रही है। (**अन्तर्बाधा**) मैने इस बात का खण्डन किया तथा उन लोगों को बताया कि ऐसी बात नही है। कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी बात नहीं कर सकती।

ऐसे सुझाव दिये गये है कि वहां पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाये। परन्तु मेरा कहना यह है कि इसके लिये यह समय उचित नहीं है। मैं प्रधान मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिये तयार हूं। परन्तु नेताओं को कुछ जिम्मेदारी से वक्तव्य देने चाहिये।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे उन निर्दोष लोगों के परिवारों से, जिनकी इन विस्फोटों में मृत्यु हुई है तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों से बहुत सहानुभूति है। उन क्षेत्रों का विकास किया जाना है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं अच्छी तरह समझती हूं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम उस क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करना चाहते क्योंकि विकास के लिये शान्ति अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति कोई सुझाव देना चाहे, मैं उसके साथ इस मामले पर विचार करने को तैयार हूं।

इस मामले की जांच अभी ही रही है। मैंने आसाम तथा नागालैंड की सरकार के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। हम गृह-कार्य मंत्रालय के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को जांच कार्य में सहायता करने तथा शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिये वहां पर भेज रहे हैं।

मैं नागालैंड सरकार द्वारा छिपे हुए नागाओं से संपर्क स्थापित करने का यत्न कर रही हूं ताकि इन दुर्घटनाओं के बारे में हम उन पर अपने विचार तथा दुःख व्यक्त कर सकें। परन्तु मुझे बताया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करने में दो अथवा तीन दिन लग जायेंगे।

माइकल स्काट के बारे में भी कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं। हम इसके बारे में पहले ही अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इस समय मैं इस के सिवाय और कुछ नहीं कह सकती कि वह शिलॉग के एक अस्पताल में बीमार पड़े हैं (**अन्तर्बाधा**) मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या रोग है।

जो लोग हिंसा के इन कार्यों के लिये उत्तरदायी पाये जायेंगे सरकार उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। यदि यह सिद्ध हो जाये कि जिन लोगों के साथ बातचीत चल रही है, वे इन हिंसात्मक कार्यों के लिये किसी प्रकार भी जिम्मेदार हैं हमें अपने समस्त दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना होगा। परन्तु निष्कर्ष निकालने में जल्दी नहीं करनी चाहिये।

मैं सभा को एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहती हूं कि देश की अखण्डता तथा लोगों की सुरक्षा के लिये सरकार सभी कदम उठायेगी।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Sir, first of all I wish to express my deepest sympathies for the families of those who have lost their lives in these accidents.

The leading role in these accidents might be that of the Pakistan nationals who have been staying in Assam illegally. Due to its weak policies Government is not taking any action to evict such persons.

Leftists are also active in those areas. Government should have strict watch over them. These leftists are also helping the Nagas hostiles.

Pakistan and France have supplied the arms to the one thousand Nagas who have returned few days ago after receiving necessary military training in Pakistan. These people can also indulge in all such activities but we should not ignore the possibility of a Pakistani hand in these accidents. It seems that Government is not prepared to take any action against the left Communists and the Pakistan nationals who are illegally staying in Assam. We should not hold any peace talks with Michael Scott and he should be turned out of the country. Government should hold a full inquiry into these accidents and take a strict action against guilty persons.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : रेलवे मंत्री को आसाम के जंगलों को साफ करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। 1956 से जंगल साफ करने की बाते चल रही है। परन्तु जैसा वचन दिया गया था जंगल साफ नहीं किये गये हैं। यात्रा करने वाली जनता को सुरक्षा की गारंटी देना रेलवे का कार्य है। मेरा निवेदन है कि यात्रा करने वाली जनता को रेलवे को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिये तथा इसकी जिम्मेदारी किसी अन्यपर नहीं डालनी चाहिये।

[श्री प्रिय गुप्त]

यह बड़े दुःख की बात है कि रेलवे मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों की सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा है। रेलवे कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया थ। कि उनको सीमा भत्ते के रूप में कुछ दिया जायेगा तथ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को बीमार राशि आदि के रूप में कुछ दिया जायेगा। परन्तु एसा कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि रेलवे कर्मचारियों को सीमा भत्ता दिया जाना चाहिये।

सरकार को सर्वप्रथम इन घटनाओं की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिये। इन दुर्घटनाओं के लिये पाकिस्तानी जिम्मेदार हैं अथवा नागा, इस बात की जांच की जानी चाहिये। जब यह बात स्पष्ट हो जाये कि इन दुर्घटनाओं के लिये कौन जिम्मेदार है तब सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

ऐसी शिकायतें है कि सरकार सूचकों द्वारा भेजी गई सूचनाओं की परवाह नहीं करती हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Naga rebellion in Assam is of quite a different nature from that of the rebellion of Adivasis, in Bastar and Gujarat. The foreign missionaries, tea planters and owners of the inland navigator companies are trying to give that revolt the shape of a revolt against the unity of India and Indian Constitution. Prime Minister should have declared some new policy towards the Naga hostiles and Mizos. Instead of doing that Prime Minister has only stressed the need of establishing peace in that area. That is not proper. Government should make a thorough revision of its policy towards the hostile Nagas and Mizos. It is absolutely necessary. I will therefore, urge that my substitute motion may be accepted.

श्री स० का० पाटिल : रेलवे कर्मचारी बधाई के पात्र है जोकि इन कठिनाईयों के बावजूद अपने कार्य पर डटे हुए हैं। इन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य को देखकर मैं महसूस करता हूं कि इनको कुछ अधिक दिया जाना चाहिये। पता नहीं और कितने दिन इन कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ेगा। मुझे बताया गया है कि जैसे किसी कर्मचारी को दूसरे रेलवे से उत्तर सीमा रेलवे में भेजा जाता है उसको दो वार्षिक वृद्धियां दी जाती है। परन्तु यह एक सामान्य बात है। उनको इन क्षेत्र में कार्य करने वे. लिये कुछ भत्ता भी दिया जाता है परन्तु मुझे इस बारे मे ठीक मालूम नहीं कि कितना भत्ता दिया जाता है। परन्तु उनके कार्य को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं हैं मैं महसूस करता हूं कि उनको कुछ अधिक दिया जाना चाहिये। इस बार में मैं कुछ कार्यवाही करुंगा।

हम नहीं चाहते कि नागाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की बदले की कार्यवाही की जाये। परन्तु हमें बहुत सतर्क होना है। ये दो दुर्घटनाएं पिछले 72 घंटों में हुई है। हमें यात्रियों के सामान आदि की तलाशी का प्रबन्ध करना पड़ेगा। हमें इन गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों से निपटने का प्रबन्ध भी करना है। यह घटनाएं पिछले 7 या 8 वर्षों की तैयारी का नतीजा हैं। सरकार को उन 13 या 14 किलोमीटर की क्षेत्र में बिछी लाइन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिये लाखों रुपये व्यय करने हैं। यह बम रखने का काम बहुत डरपोक लोगों का काम है। मैं नहीं कह सकता कि यह नागाओं का काम है। हमने वहां पर पुलों आदि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये हुए है। अब हमें ट्रंकों आदि की तलाशी का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या के बारे में मैं यही कह सकता हुं कि ये वहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार है।

मेरे सहयोगी वहां पर गये हैं और वहां की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। भविष्य के लिये हम हर प्रकार की सावधानी बरतने का प्रयत्न कर रहे है। इससे यात्रियों को कुछ असुविधा तो होगी परन्तु इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये हमें हर प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ेगी। आसाम सरकार हमें पूरा पूरा सहयोग दे रही है। सेना भी हमारे साथ है। हमें आशा है कि हम चुनौती का मुकाबला कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री राम सेवक यादव के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए / THE SUBSTITUTE MOTIONS NOS. 1 AND 2 WERE P T AND NEGATIVED.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का स्थगन पत्र प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/SUBSTITUTE MOTION NO 3 WAS PUT AND NEGATIVED.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 26 अप्रैल, 1966 / वैशाख 6, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 26th April, 1966/Vaisakha 6, 1888 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि० 6—62 लोक सभा/66—20-9-67—565